MR. CHAIRMAN: The difficulty is that there are some Members who want to speak. So, I think it is better to postpone it. We will take up the non-official business now and we will continue it later on.

15.02 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

NINTH REPORT

SHRI RAJSHEKHAR KOLUR (Raichur): Sir, I beg to move:

"That this House do agree with the Ninth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 7th December, 1977."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That this House do agree with the Ninth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 7th December, 1977."

The motion was adopted.

15.03 hrs.

RESOLUTION *RE*: PARITY BETWEEN PRODUCTION AND PRICES OF AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL PRODUCTS—*contd.*

MR. CHAIRMAN: We will now take up further discussion of the following Resolution moved by Shri Arjun Singh Bhadoria on the 24th November, 1977:—

"This House is of opinion that farmers and poor people of the country have been utterly neglected during the last 30 years and the then Government failed to keep a balance between the agricultural and industrial production. While on the one hand, there was constant decline in agricultural production and prices, on the other, the prices of industrial products constantly increased due to fictitious expenditure.

This House, therefore, resolves that with a view to maintain parity between the production and prices of agricultural and industrial products, necessary steps be taken to ensure that:—

(i) there should not be an increase of more than 10 paise per Kg. in the prices of any foodgrains during the interval between the two successive crops;

(ii) the sale-price of any essential goods manufactured in a factory should not in any case be more than one and a half times of its cost of production;

(iii) the farmer should get reasonable price for his foodgrains and other agricultural products which should meet his cost of production as well as the cost of living;

(iv) the profits of big businessmen and big agricultural farmers are curbed;

(v) ceiling on income in the private sector and Government services is imposed;

(vi) taxes such as Octroi, Sales Tax, etc. levied on essential goods are reduced; and

(vii) price policy is made effective through a four-tier and autonomous system based on socialism."

Shri Arjun Singh Bhadoria may now continue his speech. He is absent.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : सभापति जी, भदौरिया जी का जो प्रस्ताव है, मैं सिद्धान्ततः उससे पूर्णतः सहमत हूं और इसके लिये उन्हें बधाई देना चाहता हूं । इस प्रस्ताव में जो भावनायें व्यक्त की गई हैं, मैं समझता हूं कि केवल ये भावनायें इस तरफ

[श्री कंवर लाल गुप्त]

या उस तरफ की ही नहीं हैं बल्कि सारे देश की भावनाएं इस प्रस्ताव में व्यक्त की गयी है ।

सभापति जी, आप मुझ से सहमत होंगे कि भारत, दिल्ली, बाम्बे या मद्रास नहीं है । अगर सही भारत कहीं है तो वह गांवों में और देहातों में है । दुर्भाग्य से पिछले तीस सालों में, आजादी के बाद के तीस सालों में इस भारत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । अगर कोई विदेशी बाहर से आकर भारत को देखता है तो उसे भारत के दो हिस्से नजर आते हैं—एक शहरी भारत और दूसरा ग्रामीण भारत ।

MR. CHAIRMAN: Mr. Kanwar Lal Gupta, please wait a little. Let the amendments be moved. Mr. Nirmal Chandra Jain.

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN (Seoni): I move:

That in the resolution,—

omit (a) "(i) there should not be an increase of more than 10 paise per Kg. in the prices of any foodgrains during the interval between the two successive crops;"

(b) "(vi) taxes such as Octroi, Sales tax, levied on essential goods are reduced; and"

(c) "(vii) price policy is made effective through a four-tier and autonomous system based on socialism." (2)

That in the resolution,—

add at the end—

"(viii) abolish Sales Tax completely." (3)

MR. CHAIRMAN: Now, Mr. Yuvraj is not present; Mr. S. S. Das is not present. Mr. Chandra Shekhar Singh.

SHRI CHANDRA SEKHAR SINGH (Varanasi): I move:

That in the resolution,—

add at the end—

"(viii) the ratio of prices of agricultural and industrial production should be so fixed and regulated that the farmers may get remunerative price of their produce for earning their livelihood; and

(ix) the tax on agricultural land should be levied in such a manner that tax exemption is granted in case of famine, drought, flood, hailstorm and other natural calamities." (6)

MR. CHAIRMAN: The resolution and the Amendments are before the House.

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं कह रहा था कि अगर कोई विदेशी आज भारत में आए और भारत के चित्र को देखे तो उसको दो भारत नजर आयेंगे, एक तो हमारे देश का वह हिस्सा है जो गांवों में बसता है, जहां दरिद्रता है, जहां भुखमरी है, जहां गरीबी है, एक लाख 18 हजार गांव हैं जो आज भी तीस साल की आजादी के बाद पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, जहां पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता है, रहने के लिए मकान नहीं, दवाइयों का इन्तजाम नहीं है और दूसरी तरफ ओबराय होटल है, अशोका होटल है, हिल्टन होटल है और उससे आपको लगेगा कि भारत अमरीका, इंग्लैंड, जापान जैसा बड़ा देश बन गया है । लेकिन इंग्लैंड, अमरीका, जापान आदि की जो हालत सोलहवीं सदी में थी वही आज भारत की तीस साल की आजादी के बाद हालत है । भारत का समाज दो टुकड़ों में बंटा हुआ है । एक टुकड़ा वह है जहां घोर गरीबी है और दूसरा वह है जिसके हाथ में देश का सारा धन है । इस प्रस्ताव का जो भाव है वह बहुत सुन्दर है । इतिहास लिखने वाले लिखेंगे कि तीस साल लगातार आजादी के बाद भी हमारी सरकार ने देश के लोगों के लिए कुछ नहीं किया । क्या इसीलिये लोगों ने गोलियां खाई थी कि

करोड़ों लोग तीस साल के बाद भी भूखे और नंगे रहें और कुछ एक लोगों के हाथ में सारी ताकत केन्द्रित हो जाए। तीस साल का कांग्रेस का इतिहास गरीबी और भुखमरी का इतिहास रहा है। वह गीत गरीबों के गाती रही है और लोरियां दे दे कर उनको सुलाती रही है और जब वह सो जाता है तो उसके शरीर में से खून चूस कर अमीर आदमियों की झोलियां भरती रही है। यह श्रीमती इंदिरा गांधी का और कांग्रेस का इतिहास रहा है।

हमारे देश की संस्कृति बहुत पुरानी है, सभ्यता बहुत पुरानी है, धर्म बहुत प्राचीन है। लोग बहुत सहनशील हैं। अगर यूरोप होता या कोई और देश होता तो वहां शायद इस बीच में कितनी ही क्रान्तियां हो गई होतीं, ब्लडशैड हो गया होता। कई बार मुझे आश्चर्य होता है कि तीस साल आजादी के बाद भी भुखमरी को लोग सहन क्यों कर रहे है? हमारे यहां भाग्य की थ्यूरी को माना जाता है। यह लोग कहते हैं कि शायद हमारे भाग्य में ही ऐसा लिखा था। इसी कारण से वे भुखमरी की हालत को सरकार का दोष नहीं मानते हैं। गरीबी और भुखमरी दूर करने का सरकार अभी तक नारा ही देती रही है। लेकिन काम वह सरमाषेदारों के लिये ही करती रही है मैं समझता हूं कि जनता पार्टी का आज टैस्ट है, उसकी परीक्षा की घड़ी है। उसने जो वादा किया हैं कि दस साल के अन्दर हम हर एक आदमी को रोजगार देंगे, बेसिक एमेनिटीज हर व्यक्ति को दी जाएंगी इससे काम चलने वाला नहीं है। केवल दस साल के बाद यह तय नहीं होगा कि आप इस वादे को पूरा कर सके हैं या नहीं। आज से यह चीज तय होनी शुरू हो जाएगी। हर साल का लेखा जोखा आप से लिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार एक फैज्ड प्रोग्राम बनाए और हर छः महीने के अन्दर उसने क्या क्या किया है, कितने भूखे लोगों के पेट में अनाज गया है, जो तीस साल से नहीं गया था और कितने लोगों के वास्ते पीने के पानी का प्रबन्ध हो गया है। जो 30 साल तक पीने का पानी नहीं दे सके। मैंने अभी कहा कि 1 लाख 18 हजार गांवों में पीने का पानी नहीं है। आपने 6 महीने में कितना किया, कितने लोगों को रोजगार दिया? यह कहने से काम नहीं चलेगा कि अभी तो हमको 7, 8 महीने ही हुए हैं, हमने तो 10 साल कहा था। आपको फ़ज्ड प्रोग्राम बनाना चाहिये और हर 6 महीने के बाद हमारा परफौरमेंस सदन के सामने आना चाहिये कि हमने क्या किया। तब लोग हम पर विश्वास करेंगे। नहीं तो जिस प्रकार 30 साल इन्दिरा जी के नारों के बाद लोगों का विश्वास उठ गया था उसी प्रकार जनता पार्टी से भी लोगों का विश्वास उठने में देर नहीं लगेगी। हमारे लिये एक परीक्षा की घड़ी है।

प्रस्ताव में यह बात ठीक कही गई है कि किसान को ठीक दाम नहीं मिलता है। जो वह पैदावार करता है, पानी का, बिजली का और खाद का खर्चा है और जो उसकी मेहनत लगती है उसका ठीक दाम उनको पूरी तरह से नहीं मिलता। और दूसरी तरफ जो पूंजीपति हैं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी ऐसा हो रहा है, मैंने वित्त मंत्री को 35 चीजों की लिस्ट बना कर दी थी और कहा था कि जब से जनता पार्टी की सरकार हुकूमत में आयी है उन चीजों के रा-मैटीरियल में कोई भी वृद्धि नहीं हुई, फिर भी पूंजीपतियों ने अपने माल के दाम 5 परसेंट से ले कर 25 परसेंट तक पिछले 6, 7 महीनों में बढ़ा दिये हैं। क्या हमारी जनता सरकार उनसे पूछेगी कि क्यों उन्होंने दाम बढ़ाये? आज मनमाने दाम बढ़ाये जा रहेहैं, और काम जो मर्जी आये करो। यह आज नहीं चलना चाहिये। 30 साल तक वह ऐसा ही करते रहे, लेकिन अब जनता पार्टी की हवा के साथ उनकी भी हवा बदलनी चाहिये। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि आप इसकी जांच

[श्री कंवर लाल गुप्त]

कराइये कि उन्होंने क्यों दाम बढ़ाये ? मैंने तो 30, 35 चीजों के दाम दिये हैं, और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जिनके दाम बढ़े हों । कोई भी अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है तो पहले उसका जस्टीफ़िकेशन लेना चाहिये । कोई भी इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट का दाम जब बढ़ाती है तो सरकार की बगैर मन्जूरी के नहीं बढ़ना चाहिये । मैं चाहूंगा कि जो 35 चीजें मैंने बतायी हैं उनके बारे में जांच होनी चाहिये । अगर फाउन्टेन पैन की कौस्ट आफ प्रोडक्शन 1 रुपया आती है तो उपभोक्ता को कितने पैसेमें मिलेगा, इसको देखना चाहिये । यह नहीं होना चाहिये कि कौस्ट आफ़ प्रोडक्शन तो 1 रु० आये और उपभोक्ता को 10 रु० में मिले । जितनी एजेन्सियां बीच में हैं वह बन्द होनी चाहिये । हर एक चीज़ के दाम से दूसरी चीज के दाम बढ़ते हैं क्योंकि हर आदमी अगर प्रोड्यूसर है तो साथ ही उपभोक्ता भी है । हमारी सारी इंडस्ट्री खेती पर निर्भर है और जनता सरकार ने जो अपना आर्थिक प्रस्ताव किया है मैं समझता हूं कि जनता पार्टी उसके लिये मुबारकबाद की पात्र है । कुछ हमारे साथी जनता पार्टी के आर्थिक प्रोग्राम को देख कर बिदकते हैं, वह कहते हैं कि यह बड़ी इंडस्ट्री के खिलाफ है । हमने ऐसा नहीं कहा है । हमने यह कहा है कि खेती का ध्यान जो उचित तरीके से रखना चाहिये था वह कांग्रेस सरकार ने नहीं रखा है । जनता पार्टी छोटे खेतिहर का ध्यान रखे । हम ने कहा है कि हमारी इंडस्ट्री खेती पर निर्भर है, इसलिए अगर खेती का विकास होगा, तो इंडस्ट्री का भी विकास होगा, अकेली इंडस्ट्री का विकास नहीं हो सकता है । कांग्रेस पार्टी जिस रास्ते पर चलती रही है, जनता पार्टी उस से हट कर गांधी जी के बताये हुए रास्ते पर चलना चाहती है । हम सरकार से मांग करेंगे कि इस नीति का इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से होना चाहिए, किसान को ठीक दाम मिलना चाहिए और किसी भी इंडस्ट्री के मालिक को एक्सप्लायटेशन का मौका नहीं देना चाहिए ।

मेरा सुझाव है कि प्राफिट पर एक सीलिंग लगाई जानी चाहिए । मैं जानता हूं कि व्यवहार में यह मुश्किल होगा । लेकिन सरकार को यह तय कर देना चाहिए कि कास्ट आफ प्राडक्शन पर इतने परसेंट से ज्यादा मुनाफा नहीं लिया जायेगा, और अगर कोई लेगा, तो उसे दंड दिया जायेगा ।

यह बड़ी विचित्र बात है कि इस समय कपड़े पर यह छापा जाता है कि वह मिल से किस कीमत पर आया है । मैंने कई बार देखा है कि छोटे दुकानदार और ग्राहकों में लट्ठम-लट्ठा होता है--आदमी लट्ठा खरीदने जाता है, तो लट्ठम-लट्ठा होता है कि कपड़े पर तीन रुपये गज़ छपा हुआ है, चार रुपये क्यों लेते हो । मिल वालों ने एक नया ढंग अपनाया है कि तीन रुपये की जगह पांच रुपये छापने लगे हैं, और कहते हैं कि हम चार रुपये में देते हैं । मिल वालों की कितनी लागत आती है, आज इस पर कोई कंट्रोल नहीं है । मंत्री महोदय को इस व्यवस्था को बदलना चाहिए । जितनी लागत आती हैं, उस पर एक या दो परसेंट मुनाफ़ा दे कर दाम छापे जाने चाहिए, और उपभोक्ता को किस कीमत पर कपड़ा मिलेगा, वह भी छपना चाहिए । अगर ऐसा नहीं किया जायेगा, तो परिणाम यह होगा कि मिल-मालिक जितना चाहे, उतना मुनाफ़ा लेता रहेगा, और उपभोक्ता की हजामत बनती रहेगी । (व्यवधान) अगर यह चालू रहेगा, तो हमारी भी हजामत कर दी जायेगी, मैं यह वार्निंग देना चाहता हूं । इस लिए जल्दी से जल्दी यह निश्चित कर देना चाहिए कि कितना दाम कपड़ा बनाने वाली मिल को मिलना चाहिए, छोटे दुकानदार को क्या मिलना चाहिए और कनज्यूमर को किस दाम पर मिलना चाहिए ।

दिल्ली में जो टैग सिस्टम चल रहा है, वह और भी मिसलीडिंग है । कपड़े पर यह लिखा जाना चाहिए कि वह किस कीमत पर आया और उस की बिक्री कीमत क्या है, ताकि उपभोक्ता को यह मालूम हो कि उस से कितना दाम लिया जा रहा है ।

आज हालत यह है कि एक मिल 40 परसेंट देती है, दूसरी 30 परसेंट देती है और तीसरी 16 परसेंट देती है । छोटे दुकानदार को एक रुपये की जगह 1.40 या 1.16 रुपये देते हैं । एक निर्धारित सीलिंग से ज्यादा मुनाफ़ा नहीं होना चाहिए ।

सरकार ने तेल के बारे में जो प्रबन्ध किया है, उस के लिए मैं उसे बधाई देना चाहता हूं । पिछली सरकार की मैं पूरी भर्त्सना करना चाहता हूं कि उस ने तेल का घोटाला किया, तेल के लाइसेंस दे कर इलेक्शन के चंदे में करोड़ों रुपये लिये, मगर तेल नहीं मंगवाया और लोगों को लूटा । मेरा ख्याल है आप भी इस में मेरे साथ होंगे क्यों कि जो जनता के ऊपर अत्याचार करती है वह सरकार कोई भी हो अच्छी सरकार नहीं है । इसलिए हमारी सरकार को इस चीज की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि अनाज, दाल, तेल, सब्जी, कपड़ा, मकान आदि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उन की अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो । एक तो उन की पैदावार बढ़नी चाहिए । सिर्फ नारे लगाने, हड़ताल करने या फक्ट्रिया जलाने से काम नहीं चलेगा । इस के खिलाफ सरकार को यह देखना चाहिए कि हड़ताल क्यों होती है, उसके जो कारण हैं उन को दूर करना चाहिए । यह अगर किया तो मेरा तो एक सुझाव है, अभी जैसे पटेल साहब बैठे हैं या ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठे हैं, इन के पास दुनिया भर की ऐग्रीकल्चर की आइटम्स हैं, इन्हें यह पता नहीं होता कि कपड़े की एक छोटी सी आइटम कहां है । इसी तरह इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के पास हजारों तरह की इंडस्ट्रीज हैं, काटेज इंडस्ट्रीज हैं, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इतनी तमाम इंडस्ट्रीज के अन्दर कपड़े की क्या हालत है वह उन्हें मालूम नहीं हो सकती, तो मेरा सुझाव है कि एक अलग मंत्रालय बनाना चाहिए एसेंशियल कमोडिटीज के लिए जो केवल चार पांच चीजों को देखे । मकानों की व्यवस्था , कपड़े की व्यवस्था, खाने पीने की चीजों की दाल इत्यादि की, सब्जी की ऐसी चार पांच आइटम्स की व्यवस्था उस के जिम्मे हो और वह यह देखे कि हर एक चीज हिन्दुस्तान के हर एक व्यक्ति को मिलती है । इन चार पांच चीजों को बनाने से ले कर उस के डिस्ट्रीब्यूशन तक, उस के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और उस को रखने, उस के मेंटिनेंस वगैरह इन सारी बातों को देखने के लिए एक अलग मंत्रालय बनाना चाहिए जो मंत्रालय इन चीजों के ऊपर ध्यान दे । वह इस चीज को देखे कि प्रत्येक गांव गांव में एक एक चीज ठीक प्रकार से पहुंचती है, तब जा कर यह काम होगा, अन्यथा इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर है तो वह इंडस्ट्रीज में इतना लिप्त हो जाता है उस के दुनिया भर के धन्धे में कि उस को फुर्सत ही नहीं होती कि वह इस बात को देखे कि टेक्सटाइल का क्या हो रहा है ।

दूसरी चीज मैं यह कहता हूं कि सीलिंग लगनी चाहिए और वह सीलिंग आप लगाते हैं तो आप के अपने कारखाने भी हैं, आप की अपनी काटन टेक्सटाइल मिल्स भी हैं, आप को यह भी देखना होगा कि आप के अपने यहां तो गड़बड़ नहीं हो रही है । मैं आप को बता सकता हूं कि गवर्नमेंट की अपनी मिलें भी 30–30, 35–35 और 40–40 प्रतिशत मुनाफा कमा रही हैं । एस टी सी है वह तो इतनी लूट कर रही है कि कई चीजों पर दो दो सौ तीन तीन सौ परसेंट मुनाफा कर रही है । क्यों ऐसा हो रहा है ? यह ठीक नहीं है । सरकार को एक माडल होना चाहिए । सरकार को प्रोफिटियरिंग नहीं करनी चाहिए । वह सरकार अलग तरह की थी । यह सरकार जनता की है । हमें जनता के साथ मिलकर रहना पड़ेगा । जो सरकारी मिलें प्रोफिटियरिंग करती हैं

[श्री कंवर लाल गुप्त]

उन को आप ठीक करें। पहले आप अपने घर को ठीक करें उस के बाद दूसरे लोगों से अपने घरों को ठीक करने के लिए कहें।

अभी तक जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं उन में खेती में जो पैसा दिया गया है वह बहुत ही कम था लेकिन जो भी पैसा खेती में दिया गया इन पांचों योजनाओं में, आप को जानकर आश्चर्य होगा कि उस का 80 प्रतिशत रुपया केवल 20 प्रतिशत किसानों पर खर्च हुआ। इन योजनाओं में खेती के लिए दिए गए रुपये के 80 प्रतिशत का लाभ केवल 20 प्रतिशत ऊपर के किसानों को हुआ, नीचे वालों को कुछ लाभ नहीं हुआ। उसी के परिणामस्वरूप आज हमारी एक एकड़ की ईल्ड दुनिया में सब से कम है। जब तक छोटे किसान को सहायता नहीं मिलेगी, तब तक उस की एक एकड़ का ईल्ड नहीं बढ़ेगा तब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा और तब तक देश में क्रान्ति कभी नहीं आ सकती। क्रान्ति दस या बीस परसेंट किसानों से नहीं आ सकती। क्रान्ति तभी आएगी जब झोपड़ी वाले की झोपड़ी पर कम से कम छप्पर तो लग जाय, उस का बच्चा बीमार हो तो उसे दवा तो मिल जाय और उसे पानी की प्यास लगे तो पानी तो पीने को मिल जाय। यह व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

Minor adjustments here and there would not do. You will have to take very radical steps different from what they did.

और वह गलत नहीं होगा। अगर हम लीक पर चलते रहे तो पांच साल बीत जायेंगे और बाद में जनता हमसे पूछेगी कि क्या किया तो हम कहेंगे हमें नहीं पता, क्या किया। तो वह समय नहीं आना चाहिए।

पटेल साहब इस बात का ध्यान रखें कि हमारे यहां डिसपैरिटी बहुत है। गांधी जी ने यह कहा था कि प्रिंसिपुल आफ ट्रस्टीशिप में वे विश्वास करते हैं, अगर किसी के पास धन है तो वह उसको रखे, हम जबर्दस्ती छीनना नहीं चाहते, हैं लेकिन वह एक ट्रस्टी बनकर रहे। लेकिन हो यह रहा है कि जैसे मिल्स हैं और उसके जो मिल मालिक हैं व अपने पैसे का, अपनी रिचेज़ का इतना एग्जिबिशन करते हैं, धन दौलत की इतनी अधिक नुमाइश करते हैं तो गरीब आदमी जब पास से निकलता है तो कहता है कि मैं भूखा भी हूं और साथ ही हमारी बेइज्जती भी कर रहे हैं। जहां पर मैं रहता हूं वहां घर के आगे से मैं सैर करने जाता हूं तो देखता हूं तीन चार नौकर 8 कुत्ते लेकर जाते हैं। मैंने पूछा तुम्हारी क्या ड्यूटी है तो कहा हमारे पास 12–13 कुत्ते हैं और चार आदमी नौकरी पर हैं। साढ़े तीन सौ रुपया एक एक को तनख्वाह मिलती है। एक एक कुत्ते पर 12–13 रुपए रोजाना खर्चा आता है। एक तरफ तो यह हालत है और दूसरी तरफ आदमी को पीने का पानी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, बच्चे का दम घुटता हो लेकिन उसके लिए दवाई नहीं। तो यह जो हालत है वह बन्द होनी चाहिए। हम इस देश को क्रान्ति की तरफ मत ढालें। मुझे विश्वास है कि जनता पार्टी इसको ठीक करेगी, करना भी चाहिए नहीं तो हमें हटना पड़ेगा। कोई दूसरा चारा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि जो एग्जिबिशन आफ रिचेज़ होता हैं वह खत्म होना चाहिए। इस पर कोई न कोई पाबंदी लगनी चाहिए। इस तरह की पाबंदी होनी चाहिए कि एक आदनी कितनी कारें रखे, कहां तक रिचेज़ का एग्ज़िबिशन करे। मैं यह नहीं कहता कि पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाये लेकिन इस प्रकार का जो एग्ज़िबिशन है उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। एक्सपेंडीचर टैक्स शायद उतना कामयाब नहीं हुआ है, उससे कुछ और ज्यादा करना पड़ेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे

फाइनेंस मिनिस्टर जो काफी एक्सपीरिएंस्ड आदमी हैं, तजुर्बेकार हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का भी उनको अनुभव है वे समय को देखते हुए, जनता पार्टी की घोषणा को देखते हुए ऐसे डायनेमिक कदम उठायेंगे जिससे जनता पार्टी का सिर ऊंचा होगा और लोग कहेंगे कि यह पार्टी सिर्फ नारे वाली पार्टी नहीं है, काम करने वाली पार्टी है । इस तरह से एक दिन ऐसा आयेगा जब हमारा सपना साकार होगा और इस देश में सही मायने में रामराज आयेगा ।

श्री कल्याण जैन (इंदौर) : सभापति महोदय, भदोरिया जी ने इतना अच्छा प्रस्ताव रखा है कि इस पर लगातार सात-आठ दिन तक चर्चा होनी चाहिए । मैं इस सदन का नया सदस्य जरूर हूं लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यहां पर नकारात्मक चीजों पर बहस ज्यादा होती है और सकारात्मक सुझावों पर चर्चा कम होती है । पिछले तीस सालों में क्या हुआ वह हम अच्छा तरह से जानते हैं । किसानों को जो अनाज के भाव मिलने चाहिए वह भाव उनको नहीं मिले । लेकिन जब वही चीज़ मिल के पास पहुंच जाती है तो मिल मालिकों को उस चीज़ का ज्यादा भाव मिलता है । आज अगर गेहूं की लागत कीमत निकाली जाये तो कम से कम दो सौ रुपए क्वींटल पड़ती है लेकिन दुःख है कि आज किसान को 110 रुपए क्वींटल का ही भाव मिलता है । कहने का तात्पर्य यह हैं कि खेती आज घाटे का धंधा है । देश में जितने भी खेती करने वाले लोग हैं उनके लिए यह धंधा घाटे का है । सिर्फ वे लोग जिनके पास 10–15 एकड़ ज़मीन है और जिनकी आर्थिक हालत ठीक है वही थोड़ा बहुत कमा सकते हैं । गत तीस सालों में पिछली सरकार ने न कभी खेती पर ध्यान दिया और न जो खेती करने वाले लोग हैं उनके ऊपर कोई ध्यान दिया ।

मैं जनता पार्टी की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस के बारे में तफ़सील से देखे । मेरा एक सुझाव है और जो बहुत महत्वपूर्ण है—सरकार एक मूल्य आयोग बनाये, जो तमाम आवश्यक वस्तुओं की लागत-कीमत निकाल कर उसका बिक्री मूल्य निर्धारित करे । सरकार को मालूम होना चाहिए कि आज गेहूं की लागत कीमत क्या है, शक्कर की लागत-कीमत क्या है, कपड़े की लागत-कीमत क्या है, घासलेट की लागत कीमत क्या है, तमाम आवश्यक वस्तुओं की लागत-कीमत क्या है—इस काम के लिये मूल्य आयोग स्थापित करना चाहिये । हमारी जनता पार्टी की सरकार यदि इस काम को इस साल न कर सके, तो अगले साल तक अवश्य कर दे ।

आज गेहूं का भाव हम ने 110 रुपये फिक्स कर रखा है, लेकिन बाजार में 150 या 140 रुपये क्विंटल के कन्ट्रोल रेट में मिलता है, जब कि हमारे भदौरिया जी ने अपने प्रस्ताव में रखा है कि यह अन्तर 10 पैसे किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिये । यदि आप 10 पैसे नहीं कर सकते हैं तो 20 पैसे किलो का अन्तर कर दीजिये, लेकिन दो फसलो के बीच में इस से ज्यादा अन्तर नहीं होना चाहिये ।

सभापति महोदय, मैं व्यवसाय को जानता हूं, इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स लोगों से मिलता रहता हूं—एक किलो पर 20 पैसे के अन्तर से साल भर का ब्याज, भाड़ा, मुनाफ़ा सब कुछ निकल सकता है । लेकिन आज आप देखिये—तिलहन पर दो फसलों के बीच में 2 रुपये किलो का अन्तर है । गेहूं में 50 पैसे किलो का अन्तर हो जाता है—यह कहां तक उचित है ? आज हमारे पास गेहूं का बफर स्टाक है, सरकार आसानी से घोषित कर सकती है कि 120 या 125 रुपये क्विंटल में खरीदेंगे और 140 या 145 रुपये में उपभोक्ता को देंगे, इससे ज्यादा अन्तर नहीं होगा । अगर इससे ज्यादा महंगा जायेगा तो सरकार बेचेगी और सस्ता जायेगा तो सरकार खरीदेगी । इस तरह की नीति अपनाई जा सकती है । आज खाने-पीने की चीजों के नाम पर अरबों रुपये की लूट हिन्दुस्तान की गरीब जनता की होती

[श्री कल्याण जैन]

है और वह लूट धीरे-धीरे जिन लोगों के हाथों में जाती है—उन को आप सब जानते हैं । टाटा-बिरला जिन की पहले क्या सम्पत्ति थी और आज क्या हैं—आप सब जानते हैं, 1000 करोड़ से ज्यादा की सम्पत्ति हो गई है ।

इस का कारण क्या है ? इस का मूल कारण यह है कि गत 30 वर्षों में पिछली सरकार ने प्राइस-पालिसी की तरफ़ ध्यान नहीं दिया । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है—यद्यपि हमारी सरकार ने कृषि और छोटे कुटीर उद्योगों पर ध्यान देने की बात की है, लेकिन अभी तक मूल्य आयोग की स्थापना और दाम बांधने की प्रक्रिया की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है । मैं तो चाहता था कि इस बहस में ज्यादा साथी हिस्सा लेते, इस के लिये ज्यादा समय दिया जाता और जो सुझाव सामने आते, सरकार उन को कार्यान्वित करने का प्रयास करती ।

मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं —वित्त मंत्री पटेल साहब को शायद मालूम नहीं है—शक्कर के बारे में अंग्रेजों के जमाने से यह नियम था कि गन्ने और शक्कर की कीमत में 1:16 का अनुपात हो । 1954 में टैरिफ़ कमीशन ने कहा था कि शक्कर और गन्ने की कीमत में 1:16 का अन्तर होना चाहिये । आज गन्ने का भाव आप ने 12 रुपये क्विंटल फिक्स किया है, इस हिसाब से चीनी 192 रुपये क्विंटल में मिलनी चाहिये, लेकिन 400 रुपये क्विंटल में मिलती है । कहने का तात्पर्य यह है कि इस में सरकार का टैक्स है, उद्योगपतियों, मिल-मालिकों का मुनाफ़ा है, थोड़ा-बहुत छोटे और बड़े व्यापारियों का मुनाफ़ा है । आप थोड़ा सोचिये कि इस की लागत कीमत क्या है तथा इतना अन्तर कहां तक उचित है ।

भदौरिया जी ने अपने प्रस्ताव में रखा है कि कारखाने में बनने वाली सभी आवश्यक वस्तुओं का बिक्री मूल्य लागत खर्च से ड्योढ़े से ज्यादा न हो । आज बहुत से संसद सदस्यों को मालूम नहीं है कि अकेले शूगर पर सरकार का कितना टैक्स है । अभी हाल में आपने एक्साइज़ को कुछ कम किया है, उस के पहले यह एक्साइज़ ड्यूटी 121 रुपये क्विंटल थी, यानी 1 रुपये 21 पैसे एक्साइज़ ड्यूटी सरकार एक किलो पर वसूल करती थी, जब कि आम जनता, संसदसदस्य, नेता लोग, अधिकारी लोग यह समझते हैं कि दुकानदार लूट रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं । दुकानदार महंगा नहीं बेच रहे हैं, उद्योगपति महंगा बेच रहे हैं या सरकार के टैक्स ने उनको महंगा किया हुआ है । इस तरफ़ सरकार को बहुत गम्भीरता से ध्यान देना चाहिये । आज उद्योगपतियों का मुनाफ़ा एक किलो शक्कर पर 12 आने किलो है । आप ने आधी एक्साइज कम कर दी है, लेकिन बाजार में शक्कर के भाव कम नहीं हुए । मुझे खुशी होती—शक्कर की एक प्राइस बनाई जाती, सारे देश में 3 रुपये किलो में शक्कर मिल सकती ।

आज खण्डसारी वाले परेशान हैं, जो कि हमारी लेबर-इन्टेन्सिव इण्डस्ट्री है । उनकी एक्साइज़ आपने कम नहीं की । इस प्रकार से घासलेट की लागत कीमत मुश्किल से 10 पैसे लीटर है, लेकिन 1 रुपये लिटर में बिकता है । पेट्रोल की लागत कीमत मुश्किल से 12 आने या 14 आने लिटर है, लेकिन उस पर सरकार की 2 रुपया लीटर एक्साइज़ ड्यूटी है—आम जनता को मालूम नहीं है कि महंगाई का क्या कारण है । आज कपड़े में मिल-मालिक लोग अरबों रुपये की लूट कर रहे हैं । आपने भाव छापने की घोषणा की, यह बहुत अच्छी घोषणा कीथी, लेकिन इसमें वे क्या बेईमानी कर रहे हैं—मैंने मोहन धारिया जी को इस बारे में पत्र भी लिखा था—वे इसमें कास्ट-डिस्काउन्ट, रिबेट डिस्काउन्ट, ट्रेड डिस्काउन्ट के नाम पर लूट रहे हैं और यह सारा पैसा उपभोक्ता से वसूल किया जा रहा है । और मिल मालिकों की जेब में अप्रत्यक्ष रूप से चला जाता है ।

हमें दुख है कि सरकार इस तरफ़ ध्यान नहीं दे रही है। वह नकारात्मक चीजों पर ध्यान दे रही है और सकारात्मक चीजो पर वह पूरा ध्यान दें तो आर्थिक नीतियों में सुधार हो सकता है और हिन्दुस्तान के लोगों को फ़ायदा हो सकता है। उस ओर उसका ध्यान नहीं है।

उसी प्रकार से दवाइयों की बात है। स्ट्रेप्टोमाइसीन की लागत 15 पैसे पड़ती है लेकिन आज वह बाजार में एक रुपये की मिल रही है। आज जो हिन्दुस्तान में मल्टी-नेशनल कम्पनियां हैं, वे इस तरह से करोड़ों रुपये कमा रही हैं। मैंने इस बारे में सुझाव दिया है और स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मिला था कि आज जो दवाइयां "पेटेन्ट" के नाम से बिकती हैं उन से वे लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और उसके लिए सरकार हाथी कमेटी की सिफारिशों को क्यों नहीं मानती कि जो दवाई बिकेगी, उस पर कम्पनी का नाम छपा रहेगा। आज तो स्थिति यह है कि ए०पी०सी० गोली एक कम्पनी की, 10 पैसे में बिकती और दूसरी कम्पनी की, जो कि पापुलर नहीं है, एक पैसे में बिकती है। इस तरह से जो लूट हो रही है, उस पर सरकार ध्यान दे और हाथी कमेटी ने जो सिफारिश की थी कि जेनरिक नाम से दवा बिकनी चाहिए, उस को लागू किया जाना चाहिए। इसी तरह से एस्परो की बात मैं आपको बताऊं। उस के जो कन्टेंट्स हैं, वही कन्टेंट्स दूसरी दवाई के भी हैं लेकिन एस्परो 10 पैसे में बिकेगी और दूसरी दवाई एक पैसे में बिकेगी। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार इन बातों पर पूरा ध्यान देगी तो किसी चीज़ की जो लागत हैं, उसके ड्योढ़े में वह आसानी से बेची जा सकती है। मैं यह नहीं कहता कि टेलीविजन पर कर मत लगाओ या मोटर पर कर मत लगाओ लेकिन जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उनके महंगे होने का कारण यह है कि एक तो उसमें उद्योगपतियों को ज्यादा मुनाफ़ा आ जाता है और दूसरे सरकार का कर और एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा है। ये दोनों चीजें मिल कर वस्तु की कीमत बहुत बढ़ा देती हैं। मैं समझता हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी और उद्योगपतियों पर नियंत्रण रखेगी। मैं यह जानता हूं कि सरकार इसमें तुरन्त कोई बहुत ज्यादा नहीं कर सकती है लेकिन वह धीरे धीरे एक्साइज ड्यूटी को कम करे, पांच साल के अन्दर या चार साल के अन्दर धीरे धीरे वह एक्साइज ड्यूटी कम करे तो चीजों के दाम कम हो सकते है और लोगों को चीजें सस्ती मिल सकती हैं।

मैं आपको बताऊं कि एक सीमेंट की बोरी पर 5 रुपये टैक्स आता है, जिसके कारण वह इतनी महंगी मिलती है। शायद माननीय सदस्यों को मालूम नहीं होगा कि सीमेंट पर 100 रुपया प्रति टन, 5 रुपया एक बोरी पर टैक्स पड़ता है। यह तो मैंने टैक्स और एक्साइज ड्यूटी की बात बताई, फ़जूलखर्ची कितनी होती है, उसके बारे में भी बताऊंगा।

प्रस्ताव में यह भी संकल्प करने को कहा गया हैं कि किसानों को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिले और साथ ही में जो चीजें वह उपयोग में लाता है, उनको भी कम किया जाए। गन्ना सस्ता, शक्कर महंगी, तिलहन सस्ता, तेल महंगा, रुई सस्ती पर कपड़ा महंगा। ये सारी चीजें जो हैं, इनके बारे में मूल्य आयोग की स्थापना हो गई होती, तो आज यह हालत न होती। इसके ऊपर अगर सरकार ध्यान देगी, तो निश्चित रूप से जनता को बहुत ज्यादा राहत पहुंचेगी।

उसी प्रकार से, यह खुशी की बात है कि जनता पार्टी की सरकार ने खाद के भाव कम किये हैं लेकिन उन्हें और भी कम करने की जरूरत हैं। भयंकर एक्साइज ड्यूटी, 40 पैसे प्रति रुपया उस पर एक्साइज ड्यूटी है। जब ऐसा होगा, तो किसान को वह कैसे सस्ती मिलेगी। इसी तरह से आप बिजली

*[श्री कल्याण जैन]

की बात लें । बिजली बनाने में 8 पैसे प्रति यूनिट खर्च आता है लेकिन लोगों से उसके लिए 40 पैसे प्रति यूनिट और किसानों से 15 पैसे प्रति यूनिट लिये जाते हैं । जब ऐसी बात है तो कैसे गरीब लोगों को, किसानों को फ़ायदा हो सकता है और कैसे उनको सस्ती चीज़ मिल सकती है ।

अब मैं कुछ सुझाव आपको देना चाहता हूं । उद्योग पतियों का मुनाफ़ा कम होना चाहिए ।

सभापति महोदय : जरा जल्दी जल्दी करिये क्योंकि बोलने वालों की बहुत लम्बी लिस्ट है ।

श्री कल्याण जैन : सभापति महोदय, सरकार यह कर सकती है और मैं वित्त मंत्री श्री पटेल से कहना चाहता हूं,—शायद वे हिन्दी नहीं समझते और यह दुर्भाग्य की बात है क्योंकि अंग्रेजी के कारण भी देश का उत्पादन घट रहा है और देश में तरक्की नहीं हो रही है—कि कृषि के ऊपर आय कर लगाया जाए, कृषि से जो आमदनी होती है और दूसरी चीजों से जो आमदनी होती है, उस को संयुक्त जोड़ कर अगर इन्कम टैक्स लगाया जाए, तो सरकार को करोड़ों रुपये की आमदनी होगी ।

दूसरी बात यह है कि बिग बिजनैसमैनों का मुनाफ़ा कम किया जाना चाहिए और यह इस तरह से कम हो सकता है कि जो बड़े बड़े मोनोपोलिस्ट्स हैं, उनको कम से कम बैंकों आदि से फाइनेन्स न किया जाए । बहुत से संसद सदस्यों को शायद यह मालूम नहीं होगा कि जितने बड़े बड़े मोनोपोलिस्ट लोग हैं, वे अपनी जेब से बहुत कम पैसा लगाते हैं । वे रुपये में 10 पैसे ही लगाते हैं और 30 पैसे जनता के शेयर में ले लेते है और 60 पैसे बैंकों, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया और दूसरी फाइनेन्शियल कारपोरेशन्स से लेते है। कम से कम हमारे वित्त मंत्री श्री पटेल और प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई यह तो कर दें कि इलैक्ट्रिसिटी को छोड़ कर, क्योंकि उसमें पैसे की बहुत जरूरत होती है, किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए या कारखाने खोलने के लिए, इन लोगों को इन संस्थाओं से पैसा न दिया जाए । इससे बिग बिजनैसमैनों का मुनाफ़ा कम किया जा सकता है, उस को करटेल किया जा सकता है । इस के साथ ही साथ मैं यह निवदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी ने 24 तारीख को शपथ ली थी कि "अन्त्योदय" को लाएंगे आज जो ग़रीब आदमी है, वह 77 प्रतिशत ग़रीबी की रेखा के अन्दर है जबकि दूसरी तरफ़ ऐसे भी व्यक्ति है जिन पर लाखों, हज़ारों रुपया खर्च होता है । इस अन्तर को दूर करने के लिए आप को उपभोग पर रोक लगानी होगी । मेरी राय में दो हजार रुपयें से ज्यादा किसी व्यक्ति की आमदनी या तख्वाह नहीं होनी चाहिए । यह सरकार कर सकती है । इससे हम पूंजी का निर्माण कर सकते हैं । जब तक हम पूंजी का निर्माण नहीं करेंगे तब तक हम विकास नहीं कर पायेंगे । इसलिए हमें खर्च पर रोक लगानी है, उपभोग पर रोक लगानी है । जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं, चाहे व प्रधान मंत्री हों, बड़े-बड़े अधिकारी हों, किसी की भी तंख्वाह दो हजार रुपये से ज्यादा न हो । हमें इसके लिए सीमा बांधनी चाहिए ।

इसके साथ ही हमें खर्च पर भी सीमा बांधनी होगी । कोई भी व्यक्ति दो हजार रुपय से अगर ज्यादा खर्च करता है तो उस पर टैक्स लगाना चाहिए । आज लोग बड़े-बड़े खर्च कर के पूंजी का निर्माण नहीं कर रहे हैं । पूंजीपति लोग अय्याशी पर बड़े-बड़े खर्च कर देते हैं । इसके लिए जरूरी है कि खर्च पर टैक्स लगाया जाए जैसे कि पहले लगता था ।

सभापति महोदय, सेल्स टैक्स को लें । बहुत से साथियों को शायद मालूम नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में सेल्स टैक्स खाद्यान्न पर लगात

है। मुझे मालूम है क्योंकि मैं व्यापार करता हूं। मैं मध्य प्रदेश फुटकर व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूं। वहां घी पर 15 परसेंट सेल्स टेक्स है। अगर यह सेल्स टेक्स न हो तो घी 7–8 रुपये किलो मिल सकता है। अब साढ़े नौ रुपये किलो मिलता है। (व्यवधान) वनस्पति घी पर सेल्स टेक्स है। उपभोक्ता तो रिटेलर से ही खरीदेगा। उस पर 15 प्रतिशत सेल्स टेक्स है। खाने-पीने की दूसरी चीजों—दाल, तेल और खाद्यान्न—पर 12 से 15 प्रतिशत मध्य प्रदेश में सेल्स टेक्स लगता है। अन्य प्रांतों में यह नहीं है। इन खाद्यान्न की वस्तुओं पर तो कम से कम यह सेल्स टेक्स खत्म करने की सरकार पहले करे, सरकार प्रयास करे। साथ ही साथ इससे खर्च में कमी आ सकती है। आप लोग माने या न माने, इन पब्लिक स्कूलों को खत्म किया जा सकता है, रेलवे की प्रथम श्रेणी को खाम किया जा सकता है और ऐश्वर्य की दूसरी चीजों पर रोक लगायी जा सकती है।

सभापति महोदय, भदौरिया जी ने जो संकल्प रखा है उसमें कहा है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। मैं कहता हूं कि चार खंभों के ऊपर विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि पिछले तीस सालों के अन्दर कांग्रेस सरकार ने शहरीकरण किया। कांग्रेस सरकार ने बड़े-बड़े उद्योगों का निर्माण किया है। जब तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं होगा तब तक काम जनता का फायदा नहीं होगा। सौ रुपये में 80 रुपया हिन्दुस्तान की बड़ी-बड़ी जगहों के लिए खर्च होता है। दिल्ली के अन्दर डेढ़ मील बनाने के लिए सात सौ करोड़ रुपया खर्च किया गया और वह आज से 15–20 साल पहले खर्च किया गया। आज की कीमतों पर लगाया जाए तो वह सात हजार करोड़ रुपये हो जाएगा। एक पंचायत के अन्दर केवल दो हजार या चार हजार रुपया खर्च होता है। इसलिए हमें सत्ता के विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ खर्च का भी विकेन्द्रीकरण करना होगा। 25 प्रतिशत पंचायतों पर, 25 प्रतिशत जिलों के अन्दर, 25 प्रतिशत राज्य सरकारों पर और 25–30 प्रतिशत केन्द्र सरकार पर खर्च करने का हमें कोई प्रपोर्शन रखना होगा। जितने भी आय के साधन हैं उन सभी का विकेन्द्रीकरण किया जाए। इसी से सारी चीजों जुड़ी हुई हैं।

यह मैं केवल बोलने के लिए ही नहीं कह रहा हूं। मैं अपनी सरकार से अपील करना चाहता हूं कि वह गरीबी को समझे, गरीबी की आग को समझे। पिछली सरकार ने तो गरीबी के लिए कुछ नहीं किया, कम से कम यह सरकार तो आम जनता की कठिनाइयों को सरल करे और उन्हें आम जरूरत की चीज उपलब्ध कराने में रुचि ले। आज की सरकार और पिछली सरकार में अभी तो सिर्फ यही फर्क दिखाई दे रहा है कि जनता पार्टी के ऊपर के स्तर के लोग ईमानदार हैं, लेकिन सरकार की नीतियों का कार्यान्वयन जिस गति से होना चाहिए वह दिखाई नहीं दे रही है। ऊपर के स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं है लेकिन नीचे के स्तर पर यह चीज दिखाई नहीं दे रही है।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के ऊपर साथी लोग जो सुझाव दे रहे हैं उन सुझावों पर सरकार विचार करे और गंभीरता से विचार कर जनता को राहत पहुंचाए।

सभापति महोदय : देखिये, 45 मिनट अब तक खर्च हो गये है। मुझे मालूम हुआ है कि इस रिजोल्युशन को दो घंटे का समय दिया गया है। मैं मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण रिजोल्युशन है, किसानों के सम्बन्ध में यह रिजोल्युशन है। इसलिए मैं मदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे दस मिनट से ज्यादा इस पर न लें क्योंकि बोलने वाले सदस्यों की संख्या काफी है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : (बहराइच) : अगर आपको समय की सीमा ही लगानी थी

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

तो यह प्रारम्भ से ही लगानी चाहिए थी । अब क्या होगा कि बाद वालों को कम समय मिलेगा ।

सभापति महोदय : आपका चौथा नाम है । आप का बहुत सुन्दर भाषण होता है । आपका बहुत अच्छा आंट्रीब्यूशन रहता है । मैं आपका भाषण सुनना चाहता हूं । इसीलिए मैं आपको पहले बुला रहा हूं । दस मिनट में आप खत्म करने की कोशिश करें । थोड़ी बहुत इधर उधर तो हो ही जाता है ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं ज्यादा बोलने का आदी नहीं हूं ।

सभापति महोदय, आज का प्रस्ताव भारत की उन्नति से सीधा सम्बन्ध रखता है । उस में भारत की उन्नति निहित हैं ।

भारत शहरों में नहीं बसता है, भारत देहातों में बसता है । भारत देहातों का भारत है, किसानों का भारत है, शहरियों का भारत नहीं है । देश की 80 प्रतिशत से लगाकर 96 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है । बीस प्रतिशत या दस प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं और जो शहरों में रहते भी हैं वे भी गांवों से आए हुए लोग हैं जो मजदूरों के रूप में यहां रहते हैं । उन्होंने शहरों की संख्या को बढ़ा रखा है । देहातों से विवश हो कर वे शहरों में आकर रहने लग गए हैं । शहरी संख्या बहुत ही कम है । किसान की उपेक्षा भारत की उपेक्षा है ।

मैं वित्त मंत्री महोदय को और जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसने तीस साल के बाद पहली बार खेती की ओर ध्यान दिया है । किसान की और देहात की ग्रामीण जनता की आज उपेक्षा होती रही हैं । वित्त मंत्री जी ने कहा है कि बजट का चालीस प्रतिशत कम से कम देहाती क्षेत्रों पर खर्च किया जाएगा । इसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं । चालीस प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति पर खर्च करके भी वास्तव में आप गांवों की उन्नति कर सकेंगे इस में मुझे तब तक सन्देह रहेगा जब तक कि आप किसान की उपज का उसको सही मूल्य नहीं दिला पाते हैं । उसको उसकी उपज का मूल्य लागत के अनुसार नहीं मिलेगा तो आपका चालीस प्रतिशत धन किसी काम नहीं आएगा । इससे आप सड़कें बना देंगे, छोटे और कुटीर उद्योग बना देंगे लेकिन खेती पर निर्भर रहने वाले किसान जो अधिकांश में गांवों में होते हैं, उनको जब तक आप उनकी उपज का सही मूल्य नहीं देंगे वास्तव में किसानों की उन्नति नहीं हो सकेगी । आप भूमिहीनों की कुटीर उद्योग दे देंगे, लघु उद्योग दे देंगे लेकिन किसान का क्या होगा, उसकी उपज के मूल्य का क्या होगा । अगर उसको सही कीमत नहीं मिली तो वह मारा जाएगा । आज किसान मर रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है ।

किसान की खेती पर ही देश का समुचा आर्थिक ढांचा निर्भर करता है । अगर खेती की उपज नहीं होगी तो आपके जितने कल कारखाने हैं ये बन्द हो जाएंगे, किसान में खरीदने की शक्ति नहीं होगी तो ये बन्द हो जाएंगे । इनका सारा बना बनाया माल पड़ा रह जाएगा, कोई उसको उठाने वाला नहीं मिलेगा, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर तमाम देश का आर्थिक ढांचा टिका हुआ है, कल कारखानों के उत्पादन का खरीददार भी किसान ही है, गांव वाला है, वह मारा गया तो खरीददार बाजार में नहीं रहेगा, बाजार श्मशान भूमि हो जायेंगे । दूकानदार मक्खियां मारेंगे उनका माल सड़ जाएगा, दूकानों में पड़ा रह जाएगा । यह स्थिति देश की बन जाएगी । अगर देश की आपने आर्थिक उन्नति करनी है, योजनाओं को सफल बनाना है तो किसान को आपको न्याय देना होगा, उसकी उपज का सही मूल्य उसको देना होगा, उनके लागत मूल्य के हिसाब से उसको उसकी उपज की कीमत देनी होगी । आज तक यह नहीं हुआ है । मैं चाहताहूं कि आप इसको करें ।

कल कारखानों में जो उत्पादन होता है वे केवल निर्यात के सहारे टिके नहीं रह सकते हैं, चलते नहीं रह सकते हैं। देश में जो मांग है उस पर उनका टिका रहना निर्भर करता है।

प्रश्न पैदा होता है कि किसान की उपज का मूल्य कैसे निर्धारित हो। यह उसी तरह से होना चाहिये जिस तरह से फैक्ट्रियों में बने माल का होता है। कारखानों में उपज का मूल्य बहुत से दूसरे खर्च देख का निर्धारित होता है। मकान भाड़ा, मैनेजर का खर्चा, कामों का खर्चा, टी ए, डी ए, डायरेक्टरों की तनख्वाह मैनेजिंग डायरेक्टर की तनख्वाह सब का ध्यान रखा जाता है। अपने घर के आदमियों को इन पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है। किसी को पांच हजार, किसी को दस हजार और मैनेजिंग डायरेक्टर को पचीस हजार और कहीं कहीं पर चालीस-चालीस हजार रुपये तक दिया जाता है। इस प्रकार से खर्चा ज्यादा दिखा करके जो उपज का मूल्य है वह कहीं से कहीं पहुंच जाता है। और कोई पूछने वाला उनसे नहीं है। राष्ट्रपति को जितनी तनख्वाह नहीं मिलती उससे कहीं अधिक इनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स को मिलती है। इन पर कहीं रोक टोक है? नहीं है। लेकिन किसान पर यह सिद्धान्त लागू नहीं होता। कल कारखाने के माल के लिये तो आपने कह दिया कि तुम्हारी जो लागत आयेगी, खर्च होगा उसके हिसाब से मूल्य निर्धारित होगा और फिर जो माल बाजार में आयेगा कम्पटीशन होगा उसका अधिक से अधिक दाम उनको आयेगा। लेकिन किसानों के माल का दाम निर्धारित करने के लिये आपने ऐग्रीकल्चर प्राइसेज़ कमीशन बनाया हुआ है जिसमें तमाम शहरी अधिकारी हैं, जिन्होंने खेत नहीं देखा और किसान को समझ नहीं कि उनका क्या खर्चा आता है, वहां यहां कमरों में बैठकर उसके कीमत लगाते हैं। वह देखते है खाद पर कितना लगा, पानी का क्या मूल्य हुआ, हल चलाने का क्या हुआ। लेकिन वह पता नहीं है कि उसका पूरा परिवार खती में लगा हुआ है, उनकी तनख्वाह क्या होगी? उनके परिश्रम की तनख्वाह नहीं लगायी जाती है। और जो दाम आप तय करते हैं वह भी उसको पूरी तरह से नहीं मिलता। गेहूं का मूल्य क्या हो इसका निर्धारण पंत यूनिवर्सिटी और पटियाला ऐग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी ने हिसाब लगाकर बताया है कि 1 क्विंटल गेहूं की पैदावार पर 120 रु० लागत आती है। लेकिन हमारी सरकार की जो कमेटी बैठी हुई है उसने किसानों के माल का मूल्य निर्धारित किया है 75, 80, 90 रु० और आज कृपा कर के 110 रु० तय किया है। यह पिछले तीन साल के आंकड़े हैं जब कि यह खर्चा बढ़कर आज 200 रु० हो गया होगा। लेकिन आपने 110 रु० दाम रखा है। और जो खरीद के सेन्टर बनाये हैं वहां किसान गाड़ियों की कतार लगाये खड़े रहते हैं और जो खरीद करने वाले आपने बैठायें हैं वह व्यापारियों से मिले रहते हैं जिसकी वजह से उनका माल 110 रु० क्विंटल पर नहीं लिया जाता जिसके कारण उनको अपना माल वापस ले जाना होता है और मजबूरन बिचौलिये को 90 रु० पर बेचना पड़ता है। उसी माल को थोड़ा सा साफ़ करके वही एजेन्ट 110 रु० पर बेच देता है। इस प्रकार मिल कर किसान को लूटा जा रहा है। इस प्रकार क्या आप किसान को जिन्दा रख सकेंगे?

वित्त मंत्री जी अर्थ-शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, कभी आपने हिसाब लगाया कि किसान की कपास सस्ती और उसका कपड़ा बन कर आता है तो कितना गुना मुनाफ़ा मिल मालिक लेते है? गन्ना आज 8 रु० क्विंटल के भाव लिया जा रहा है मिल मालिकों ने सलाह कर ली है कि माल अभी नहीं लेंगे, और किसान ने अगर अपनी ईख नहीं काटी तो वह गेहूं की फसल नहीं ले सकेगा। इसलिए मजबूरन अपनी ईख को फसल किसान काट रहा है और अपना गन्ना खंडसारी वालों को दे रहा है जो 6 रु०, 7 रु० क्विंटल के भाव से ले रहे है और इस पर भी

[ओम प्रकाश त्यागी]

1 रु० ढुलाई का काटते हैं । इस प्रकार किसान को अपने गन्ने का दाम 5 रु० क्विंटल ही मिल रहा है। आपने गन्ने का दाम निर्धारित किया 8 रु० क्विंटल जब कि जलाने की लकड़ी का दाम है 20 रु० । क्या आपने कभी सोचा कि किसान कैसे जिन्दा रहेगा ? आपने उसकी हालत का ध्यान नहीं रखा ।

शहर में फ़ैक्ट्रियों के मालिकों को दिन में बिजली मिलती है और वह आराम से अपने बंगलों में सोते हैं । लेकिन किसान को जानबूझ कर रात में बिजली दी गई है जिसकी वजह से जाड़े की रात में बेचारा किसान नंगा रह कर अपने खेत में पानी लगा रहा हैं । कभी बाढ़ आ जाती है और कभी सूखा पड़ता हैं। आज हालत यह है कि हम लोगों ने किसान को मार दिया है। उसे तो गन्ने की लागत भी नहीं मिल रही है, और चीनी मिल-मालिकों द्वारा 8 रुपये क्विंटल के हिसाब से गन्ना लेने के बाद भी चीनी 400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही है। सरकार कहती है कि हम राशन की दुकानों पर चीनी कंट्रोल रेट पर दे रहे हैं। शहरियों को दे रहे हैं, लेकिन देहात वालों के पास चीनी कहां पहुंच रही है ? ब्लाक लेबल पर जो लोग बैठे हुए हैं, वे किसानों के फ़र्ज़ी नाम लिख कर चीनी को ब्लैक में बेच देते हैं, और किसान को बाज़ार में चीनी 400 रुपये क्विंटल के हिसाब से मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार के पास इसका क्या जवाब है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन सा दिमाग है, जिसने गन्ने का दाम 8 रुपये रखा है। ऐसे दिमाग को म्यूज़ियम में रखना चाहिए। आज किसान को मारा जा रहा है। उसकी पैदा की हुई कपास और मूंगफली सस्ती है, लेकिन मूंगफली के बने हुए डालडा के दाम आसमान को छ रहे हैं। सरसों का तेल 15, 16 रुपये किलो पर भी नहीं मिलता है। बीच में डाकू लोग किसान को लूट रहे हैं, और सरकार न जाने क्यों इस बात को नज़र-अंदाज़ कर रही है।

वर्तमान सरकार ने किसानों के साथ जो हमदर्दी दिखाई है, उसे व्यवहार में परिणत करना चाहिए। किसान को कम से कम लागत तो मिलनी चाहिए। किसान की उपज का मूल्य निर्धारित करते समय खाद के रेट गवर्नमेंट द्वारा निश्चित रेट के हिसाब से लगाये जाते है। लेकिन मैं देहात में देख कर आया हूं कि ब्लाक लेबल पर जो खाद भेजी जाती है, वे लोग उसे ब्लैक मार्केट में व्यापारियों को बेच देते हैं। किसानों को फ़ासफ़ेट, सलफ़ेट या यूरिया आदि रत्ती भर भी खाद नहीं मिली, जबकि उन्हें गेहूं की फ़सल बोने के समय खाद की ज़रूरत पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट लेबल पर भी—मेरठ कमिश्नरी में—मैंने पाया है कि वहां खाद नहीं है। पूछने पर वे लोग कहते हैं कि खाद आई नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि बाज़ार में दुकानदारों के पास ब्लैक मार्केट में खाद कैसे मिल जाता है। इसके मानी ये हैं कि अफ़सरों ने बिज़िनेसमैन के साथ सांठ-गांठ की हुई है। ब्लाक लेबल पर भी यही स्थिति है। वे सब मिल कर किसान को मार रहे हैं।

15.58 hrs.

[SHRI TRIBID CHAUDHURI *in the Chair*]

कृषि-उत्पादन का मूल्य निर्धारित करते समय अन्य चीज़ों के मूल्यों के साथ उसका अनुपात रखना चाहिए। मैं बड़े लैक्चर सुनता हूं कि देश में बहुत महंगाई है, महंगाई से देश को बचाओ। इसके लिए शहर में आन्दोलन किये जाते हैं, जलूस बना कर यहां लाये जाते हैं, और मांग की जाती है कि अनाज और तेल आदि को सस्ता किया जाये, अर्थात् किसानों की पैदा की हुई खाने की चीज़ें सस्ती की जायें। कोई यह नहीं कहता है कि

किसान जो कपड़ा, ट्रेक्टर आदि चीजें बाहर से खरीदता है, उन्हें भी सस्ता करो, क्योंकि उनका सम्बन्ध शहरों से नहीं है।

सरकार शहरों का ख़याल करके महंगाई और सस्तेपन को आंक रही है। यदि वह शहरों का ख़याल करके किसान द्वारा पैदा किये हुए गेहूं, तेल और मूंगफली आदि को सस्ता करेगी, तो मैं बताना चाहता हूं कि धर्म का सिद्धान्त यह है कि जो आदमी धर्म को मारता है, धर्म उसे मारता है। आप किसान को मारेंगे तो किसान इस देश को लड़खड़ा देगा और फिर कोई भी सरकार हो वह ठहर नहीं सकेगी।

16.00 hrs.

मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। मेरा यह सुझाव है कि मूल्य निर्धारण करने वाली जो कमेटी है उसमें शहरियों की जगह देहात के आदमियों को रखिए जो ताकि किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिल सके औगर उसका जो रा मैटीरियल है उससे बनी हुई वस्तु जो आती है उन दोनों के दाम में एक अनुपात होना चाहिए। अगर उन दोनों के दाम में जमीन आसमान का फर्क रहा, सैकड़ों गुना कीमत उसकी हुई तो यह चीज ज्यादा दिन चलेगी नहीं। परिणाम क्या होगा कि आज सरकार हमारे हाथ में है, आराम से चल रही है, लेकिन आप ने उपेक्षा की किसान की और किसान गरीब हो गया, निर्धन हो गया, उसके पास ओढ़ने और पहनने के लिए कपड़ा नहीं रहा, रहने के लिए मकान नहीं रहा, उसकी हालत खराब हो गई तो मैं आपको चेतावनी देता हूं इस देश में खूनी क्रान्ति हो जायेगी और वह खूनी क्रान्ति का नारा लगाने वाले बीच में बैठे हुए हैं। वे इस बात की तलाश में हैं। इस देश में ऐसी पोलिटिकल पार्टीज हैं जिनका यह नारा है कि पोलिटिकल पावर कम्स थ्रू दि बैरल आफ ए गन, जिनका नारा है असंतोष। फैक्ट्रियों में असंतोष, किसानों में असंतोष हर जगह असंतोष हो जायेगा तो आटोमेटिकली खूनी रेवोल्यूशन हो जायेगा। अगर इस देश को उस खूनी क्रान्ति से बचाना है तो आपको किसानों को बचाना होगा और किसानों को बचाने के लिए आप को किसानों के उत्पादन का सही मूल्य देना होगा। अगर वह नहीं दिया तो वह क्रान्ति हो कर रहेगी।

मैं पटेल साहब से कहूंगा कि वह बम्बई की सड़कों और गलियों को छोड़ कर एकाध-बार मेरे साथ किसानों के बीच मे चलें तो उनकी बेचैनी आपके सामने आये। आज उसके पास ओढ़ने को कपड़ा नहीं है, रहने को झोपड़ी नहीं है। 66 रुपये महीने की मजदुरी उसको मिल रही है। 76 पैसे, 96 पैसे रोज़ की मजदुरी मिल रही है। देहातों में चल कर आप देख लीजिये। आप ने निश्चित कर दिया कि पांच रुपये मज़दुर की दैनिक मज़दुरी हो, लेकिन उसको मिल कितना रहा है यह चल कर देख लीजिए। आज मजबुरी में वह किसान के यहां बन्धक के रूप में काम कर रहा है, तो रोटी पर काम कर रहा है। उसको एक टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा है। कब तक वह इंतजार करेगा? ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। अपने उद्धार के लिए जहां उसे सहारा मिलेगा वहीं चला जायेगा। मुझे डर है कि जिस प्रकार से माओ-त्से-तुंग ने किसानों का सहारा लेकर चीन में रेवोल्यूशन कर दिया था वही स्थिति कहीं भारत में भी न हो जाये। इसलिए मैं आप को समय पर चेतावनी दे रहा हूं और आप को समय रहते संभलना चाहिए। अगर यहां खूनी क्रान्ति हुई तो इसका उत्तरदायित्व सरकार पर होगा।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : यह तो बड़ा ही अहम प्रश्न है कि जो लोग संशोधन पेश करें वे अपनी बात भी न कह सकें।

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Mr. Chairman, Sir, after carefully going through the resolution moved by Shri Bhadoria, I feel there is a need to discuss and participate in this discussion.

MR CHAIRMAN: Mr. Lakkappa, one minute. We have about less than 1 1/2 hours only, and the list of speakers ...

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH: I am not speaking about the list of Speakers. I said, we have moved the amendments and that should be taken up.

MR. CHAIRMAN: But that is not the procedure. We will see how far you can be accommodated.

SHRI CHANDRA SHEKHER SINGH: That means, they will not be permitted to be moved. We shall have to talk about it.

MR. CHAIRMAN: Provided time is available.

SHRI CHANDRA SHEKHER SINGH: Otherwise, not?

MR. CHAIRMAN: Yes. The practice in the House has been that hon. members who move amendments are not necessarily permitted to speak. They speak if time is available.

श्री नाथू सिंह (दौसा) : सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि इसका समय बढ़ा दिया जाये क्योंकि बोलने वाले ज्यादा हैं और यह विषय महत्वपूर्ण है ।

MR. CHAIRMAN: That is in the hands of the Speaker.

SHRI K. LAKKAPPA: The mover of the resolution has done a good service by bringing it. I remember we were members of the Lok Sabha together and there was an element of socialist character in him. Otherwise, he would not have brought such a resolution.

The country today is divided into certain economic divisions. There are big business houses operating on one side and the poor masses. the weaker sections, agriculturists, small and marginal farmers and have-nots struggling on the other. So, to bring about a parity among these forces, certain legislation is necessary. Also, a certain socialist approach is necessry. That spirit has to be engendered and acted upon. The Janata Party, to which the hon. member belongs, really ownes certain responsibilities and social obligations to discharge towards the common people. The have-nots, the small and marginal farmers, agricultural labourers and other weaker sections should control the entire machinery in this country. The biggest machinery is this Parliament. We find that the representatives of big business houses and monopolists are more in number. The poor people cannot prevent the way the money-bags operate in this country. When that is the situation, now can we expect any social legislation to be passed by this House? That is our struggle. The country should have economic freedom. Everyone has to fight for equality of economic freedom. That is lacking today because of the stranglehold of big business houses, monopolists, hoarders, and blackmarketeers. Even the land reforms have been scuttled by backdoor methods. In joint families, the big landlords are distributing the land amongst themselves. The agricultural economy has operated in such a manner that it is still under the control of the business people. In every town you can see how business houses are operating, how speculative practices are indulged in and how the prices of essential commodities are fixed. By virtue of their money power, they are able to control the trading policy and everything. Unless every citizen is enable to participate in the

economic system of the country, merely having the right to vote is of no use. The landless people have got the right to vote, but what is the use? But they do not have any right to determine or control the entire machinery of the Government today, even though we have got democracy only in name. Today it is the Janata Party which is running under the thumb and control of the big business houses. I think that they control the steering of the government. You can see every day discussions going on about the prices. But the price structure should be determined by the will of the farmers, the growers and the landless labourers, but it has never been determined by them. Everything has either been put off or referred to tribunals or it has been left to the fancy and mercy of the bureaucracy of this country. In these circumstances, how can poor farmer or grower get his price?

Sir, there are a number of breweries functioning in this country today and if their cost of production is one rupee, they sell it at Rs. 15/- and they supply a good number of drinks to the Defence personnel. By charging more, they get a lot of money from the taxpayers. But nobody determines what is the cost of production. The poor people have to pay more for all the essential commodities and other necessities of life without knowing the exact prices of these essential things. Indeed, the prices have gone up like anything. I want to ask: Is there any machinery to control the prices? Is there any machinery to determine the prices? It is all a show. We have been seeing for the last 8 months that prices have been going up and no action has been taken to curb the upward trend of prices. Every time they say that we have to gamble with the monsoon. When there is a good monsoon and we have got good water and good crop, again the poor farmer will be the hard-hit because the hoarders will start operating by purchasing everything and hoarding the foodgrains. These are the very people who worked for the restoration of democracy or whatever you call. I do not know what sort of democracy they have restored by bringing back the hoarders and blackmarketeers in a different garb. Our fight is an unending one. The fight is on and we are determined to fight against casteism, against capitalism, and against reactionary activities or any such thing by which you are preventing economic growth and freedom of the people of this country. Our struggle against all such things is continuous and it will not be stopped. If there are many people of understanding in your Party, I warn them and at the same time request them that they should not allow this Government to be run by these big business houses and hoarders. If they do so, they will be in trouble.

Sir, Mr. Bhadoria in his Resolution has also suggested that "the sale price of any essential goods manufactured in a factory should not in any case be more than one and a half times of its cost of production." It is not a question of determining alone, but it is a question of controlling. My friend, Mr. Dharia stated nearly a hundred times on the Floor of this House that there will be a proper public distribution system. What happened to that public distribution system? He said that there will be a proper public distribution system. What has happened to it? Is it going to be done through the cooperatives or fair price shops controlled by the Government? Even this has not been determined by the Government for the last 8 months. Every day Government is saying that it will be there, but it is not there. I am also going to introduce the same type of bill.

If it is a question of an ideology or taking socialist action. I will always support you. We are supporting all socialist measures, and will contribute to support them. There will be no second thoughts on this.

Now about land reforms. How many people in this Government have

[Shri K. Lakkappa]

got belief in land reforms? Very few. There are 5 constituents in the Government. Mr. Charan Singh represents the Kulaks; and my friend the Finance Minister has his ideas which are very old. There are other elements also, *viz.*, Ananda Margis, Jana Sanghis etc. They never believed in land reforms. Traders, hoarders and black-marketeers are growing in number, in every city. What is said in this Resolution is highly impossible, unless there is a change in the character of the Government which is composed in the manner I have indicated. Has there been any determined effort? Is it visible in any of their actions? I don't see any such action, except the appointment of Commissions. There has been no progressive legislation passed, or measures taken. What is the legislation passed during the last 8 months to benefit the poor people and farmers *e.g.* in the matter of determination of prices, fixation of tariff, regular payment of wages or even solving industrial disputes? Please search your hearts and tell me.

The present Government is taking action against the previous Government, arresting people and using the same old MISA or Mini-MISA—in whatever form it may be—in Madhya Pradesh and Kashmir. How much money is Government spending on these commissions? More than Rs. 1 crore, for nothing. There is no expenditure of money for helping the farmers or for fixing of prices for the poor people and workers in the country. If such actions had been done, people would have appreciated this Government. In their absence, what kind of appreciation can you expect for this Government? This Resolution wants private entrepreneurs, big businessmen and big agricultural farmers to be curbed. How can it be done? What is the machinery available for it? Friends on the opposite side say that they were operating in the previous government also. Probably they might have re-organized themselves and got infiltrated in the Government. If they were in the government of my party, I would attack them.

Now about the ceiling on private incomes. The present Government does not believe in the philosophy of strengthening the public sector. They might say that they also very sincerely desired the growth of the private sector. This kind of appeasing the private sector in the manufacture or production of necessities of daily life cannot help the country, because the aims and ambitions of big business is to make huge amounts of profit. Therefore, I think the Finance Minister must understand the feelings of the people of this country, and change his outlook at least for the sake of the people. I do not criticise the person. But you are having certain thoughts. Those thoughts will not help this country unless you change your mind and make a thorough change according to the needs of the society. You must change the entire system, make it more amenable and available to the people of this country. The natural resources are in abundance and we can exploit the natural resources. So far as availability of foodgrains and essential commodities are concerned, everywhere these are available but you have to pay through your nose. If you pay a very high price, you can get any damn thing. Unless this system is regulated it is impossible to control the deteriorating situation, the alarming situation that has been created by this Government. I want you to come out with progressive measures with determination. You must streamline the administration. I want all types of taxes, which have been imposed on farmers to go. Because of these taxation measures, sales-tax, income-tax, all types of taxes, the farmer feels over-burdened and he is deserting his profession and going in some other speculative trade. The agriculturists, the small farmers, the middle class farmers, all are deserting their profession. If the prices of the inputs are not controlled, you will see that there will be shortage of foodgrains in spite of the fact that

natural resources are available, manpower is available and even the Government is functioning. Therefore, I am requesting the Government that you must see that the farmer, the backbone of this country, should be respected and helped in every way.

The Government should come forward with progressive policy and see that all the farmers of this country are freed from any kind of exploitation.

With these words, I congratulate the mover of this resolution.

MR. CHAIRMAN: Two hours have been allotted for the discussion on this resolution. We have barely 35 minutes left. How much time the Minister will take?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): About 15 minutes.

MR. CHAIRMAN: How much time the mover of the Resolution will take?

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : कम से कम आध घंटा या जितना समय वित्त मंत्री जी लेंगे, उतना समत तो लूंगा ही

श्री नाथू सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का समय बढ़ा दिया जाए ।

MR. CHAIRMAN: We can go upto 5.30 because at 5.30 half-an-hour discussion has to be taken up. The mover will also have his right to reply. So, at least, half-an-hour for the Minister and the mover of the resolution has to be kept. Now, there would be very little time for many speakers to be accommodated. I am sorry, I have got a very long list and many of them cannot be accommodated.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Cannanore): We have heard the Janata Members as well as the Congress Members. Members from the CPIM are here; we are also here.

*SHRI S. JAGANNATHAN (Sriperumbudur): Mr. Chairman, Sir, I am grateful to you for having given me an opportunity to participate in an important discussion on the Resolution demanding parity between the production and prices of agricultural and industrial products. On behalf of my party, the All India Anna Dravide Munnetra Kazhagam, I would at the very outset pay my humble compliments to Shri Arjun Singh Bhadoria who has focussed the attention of this House on such an important issue.

Sir, none of us can deny that the basic raw materials of all industrial products in our country are agricultural products and we cannot afford to denigrate their importance in our economic planning. While the cotton growers are groping in the dark, the textile mill-owners are making merry. The mill-owners are interested only in manipulating the profits for their personal aggrandisment. They do not care to pay remunerative prices to cotton growers. They are positively inimical towards the welfare of mill workers. They have no compunction towards the weavers. You please see the price paid to cotton and the price of cotton cloth. The gulf between the two is unbridgeable. Similarly, while the ground-nut growers are not able to lift themselves above the earth, the groundnut oil producers are floating in heaven and high-seas. The tobacco-

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri S. Jagannathan]

cultivators are trembling on account of soaring costs of cultivation. But the cigarette manufactures never cease to mint money and that too with the slogan of 'smoking is injurious to health'. I can compare such differences only with the difference between a mountain and a meadow.

I will give another illustration. During the period of Emergency, in one month the industrialists declared voluntarily unaccountable money of Rs 1,500 crores. From where did they get this money? They fleece the customers and floor the producers of basic raw materials so that they are able to flourish. They collect taxes from consumers but evade payment of taxes to the Government. While the producers are basic raw materials have been battered by the fury of Mother Nature, while they swim in swirling waters of flood and stink and starve during drought, the industrialists are engaged in massing black-market money in the cool comfort of air-conditioned rooms.

The agriculturists are not getting remunerative prices. The workers are not getting minimum wages. If they are to get fair wages, they have to resort to strike. The consumers are the casualty in the cost-structure of industrialists. They multiply their wealth by many hundred times through any means—cheating the people and deceiving the Government. Who are these neo-rich of our independence-era? None can deny that the industrialists are the neo-rich class in our country.

The great leaders of Janata Party are repeatedly saying that they are going to re-orient the Indian economy. The refurbished Central Planning Commission says that the urban-based economy would become rural-biased. I have to say that the payment of fair prices to agricultural products is not a political problem. The future of the country is involved in this. What the Congress Government and the D. M. K. Government could not do in Tamil Nadu in 30 years, our great leader, Thiru M. G. R. is trying to do in Tamil Nadu. The eradication of penury is his soul-breath. The agriculturists and the industrial workers are his two eyes. He has dedicated his life in the service of 4.5 crores of Tamil people. While supporting the Resolution of Shri Arjun Singh Bhadoria, I would like to appeal to the Central Government that the sinews of our leader Thiru M. G. R. must be strengthened by the senior leaders in the Government of India.

With these words I conclude my speech.

श्री नाथू सिंह (दौसा) : सभापति जी, इस प्रस्ताव के रखने पर मैं माननीय अर्जुन सिंह भदौरिया जी को बधाई देता हूं क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस देश में 80 प्रतिशत किसान हों, जो देश गांवों का देश हो, जिस देश के विकास की रीढ़ की हड्डी खेती है, मुझे दुख है कि पिछले 30 साल से जो सरकार किसान का नाम लेकर हुकूमत करती रही उसने पीछे से किसानों की पीठ में छुरा भोंका। चाहे सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उस सरकार ने किसानों को धोखा दिया। यही नहीं किसानों का शोषण किया और शोषण करवाया। किसानों में जागृति नहीं आने दी, उनको पिछड़ा और गरीब बना कर रखा ताकि वह समझ नहीं कि देश क्या है, लोकतंत्र क्या है, सरकार क्या है, और अंधेरी रात में किसान भटकता रहे और कांग्रेस हुकूमत करती रहे। किसानों के पीछे एक बहुत बड़ा षड़यंत्र काम कर रहा था। लेकिन एक समय आया और आज जिन किसानों के आंसुओं की कीमत कांग्रेस सरकार नहीं समझ सकी उन किसानों के आंसुओं की नदी आयी और कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार को बहा कर हिन्द महासागर में ले गई। यही कारण है कि आज भी कांग्रेस की बैंचेज सामने खाली पड़ी हुई हैं।

पहले कांग्रेस पूरे देश पर हुकूमत कर रही थी, लेकिन अब वह कहने लगी कि हम दक्षिण में हैं। दक्षिण में कहां ? हिन्द महासागर में। आर्थिक, राजनीतिक रूप से किसानों का शोषण किया गया, किसानों का शोषण करने वाले लोगों को उनका प्रतिनिधि चुनकर लोक सभा में लाया गया। सामाजिक दृष्टि से उनको शिक्षा नहीं दी गई, उनमें जो रूढ़ियां चली आ रही थीं उनको दूर नहीं किया गया। नारे देते गये कि गरीबी हटायेंगे, किसानों की दशा सुधारेंगे। लेकिन गांवों में उनके बच्चों को पढ़ाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की। बड़े-बड़े विश्वविद्यालय खोले, दिल्ली में जे०एन०यू० खोली, लेकिन गांवों में एक भी कृषि विश्वविद्यालय नहीं खोला, कृषि कालेज नहीं खोला। जे०एन०यू० पर इतना पैसा खर्च किया गया। उसके बजाय अगर गांव में कृषि कालेज खोला जाता और वहां शिक्षा दी जाती तो कितना फ़ायदा होता। मां बाप बच्चे को पैदा कर देते हैं। लेकिन उसका भरता-पोषण किसान करता है। उस दूसरे मां बाप की हत्या कांग्रेस सरकार ने की। किसान का बेटा देश की सीमा पर भी लड़ता है, वहां पर भी अपना खून बहाता है, और देश की आंतरिक सीमा में गरीबी और भुखमरी से भी लड़ता है। दुर्भाग्य है इस देश का कि एक तरफ़ लोग एयर कंडीशन्ड कारों में बैठते हैं, दूसरी तरफ़ देश का किसान बिना कपड़ा पहने, चिलचिलाती धूप में अपने खेत में हल चलाता है लेकिन फिर भी उसे अपने पेट की अग्नि मिटाने के लिये रोटी का टुकड़ा नहीं मिलता। इसकी जिम्मेदारी भूतपूर्व सरकार पर है, और मैं मांग करता हूं कि जिस तरह से इन्दिरा गांधी पर शाह आयोग बैठाया गया, और घपलों के लिये विभिन्न आयोग नियुक्त हुए, उसी तरह से किसान की पीठ में छुरा जो भोंका गया, उन्हें दबाया गया, इसकी जांच करने के लिये कि किसान आज तक क्यों पिछड़ा रहा, उसको किस तरह से धोखा दिया गया, उसका शोषण किया गया, अधिकतर नसबन्दी भी किसान के बेटों की ही की गई, इन सब की भी जांच कराई जाये। पिछली सरकार ने किसानों का कितना शोषण किया इस बारे में भी एक जांच आयोग बिठाना चाहिए।

इस देश में गांवों का विकास कैसे हो, जब तक वहां सड़कें न पहुंचें और सिंचाई की व्यवस्था न की जाये ? किसानों की पैदावार तब तक नहीं बढ़ सकती है, जब तक उसके खेत को पानी और बिजली न मिले। लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। किसानों को खेती का आधुनिक तकनीक नहीं सिखाया गया। कुछ ग्रामसेवक गांवों में भेज दिये गये, लेकिन कोई सामान नहीं दिया गया। सड़कें बनाने के लिए पैसा मंजूर किया गया, लेकिन सड़कें केवल कागज़ पर बनाई गईं, और जब स्थान पर जा कर देखा गया, तो बताया गया कि सड़क बाढ़ में बह गई। इसी तरह बांध भी केवल कागज़ों पर बनाये गये हैं। जांच करने पर बताया जाता है कि बांध में कीड़ा पड़ गया था, उसे मारने के लिए दवा डाली गई---उस दवा के पैसे भी खा गये---लेकिन कीड़े खत्म नहीं हुए और बांध को नहीं बचाया जा सका। या यह कहा जाता है कि ज्यादा पानी आ गया, इसलिए बांध टूट गया। किसानों को तो कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों के पेट भर गये। इसी तरह गांवों को नहरें नहीं दी गईं।

गांवों को बिजली रात को दी जाती है, जब कि कारखानों को दिन के समय बिजली दी जाती है, जहां वह रात के समय भी दी जा सकती है। मुझे बड़ा दुख है कि टाटा और बिड़ला के बड़े-बड़े उद्योगों को बिजली सस्ते रेट पर दी गई। शुरू-शुरू में उन्हें 3 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दी गई, और किसानों के खेतों को बिजली 13 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दी गई। फिर उसको बढ़ा कर 18 पैसे, फिर 25 पैसे और फिर 30 पैसे

[श्री मत्थू सिंह]

प्रति यूनिट के हिसाब से दी गई, और किसानों के खेतों की बिजली 13 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दी गई। फिर उस को बढ़ा कर 18 पैसे, फिर 25 पैसे और फिर 30 पैसे किया गया। आज उन्हें बिजली 32 पैसे प्रति-यूनिट के हिसाब से दी जाती है, जब टाटा और बिड़ला के बड़े-बड़े कारखानों को वह 7 या 10 पैसे प्रति-यूनिट के हिसाब से दी जाती है। आखिर किसानों के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जाता है ?

पिछली सरकार ने यह कोशिश नहीं की कि किसानों को सस्ते ट्रेक्टर दिये जायें। लेकिन संजय की छोटी कार बनाने के लिए न जाने क्या क्या दे दिया गया, हालांकि वह कार नहीं बनी। क्या इस देश का भूखा, झोंपड़ी में रहने वाला किसान छोटी कार में बैठकर घूमेगा ?

गांवों में मंडियां नहीं बनाई गईं। किसान को अपना अनाज बेचने के लिए मीलों दूर शहरों में जाना पड़ता है, जहां उसे लूटा जाता है। अगर गांवों में छोटी-छोटी कृषि-उपज मंडियां बनाई भी गईं, तो उनकी बिल्डिंगों पर लाखों रुपये खर्च कर दिये गये। मैं अपनी कांस्टीट्युएन्सी का उदाहरण देना चाहता हूं। झोंपड़ियों में रहने वाले किसानों के लिए कृषि उपज मंडी की बिल्डिंग लाखों रुपये खर्च करके बनाई गई, जिसमें किसान को घुसने नहीं दिया जाता है, उसमें केवल बड़े-बड़े पदाधिकारी या व्यापारी ही जा सकते हैं। मीटिंग हाल बनवा दिये गये। इतना अन्याय। पशुधन बढ़े, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। डेयरियों का विकास नहीं किया गया। क्या दिया आखिर किसानों को ?

व्यापारी यूनियन बना कर अपने अधिकारों के लिए लड़े, मजदूर अपनी यूनियन बना कर अपने अधिकारों के लिए लड़ें, विद्यार्थी यूनियन बना कर अपने अधिकारों के लिए लड़ें लेकिन बेचारा किसान ऐसी हालत में है, आवागमन के साधन उस के पास नहीं, पैसा उस के पास नहीं, अपनी यूनियन वह बना नहीं सकता, एक साथ बैठ नहीं सकता और अपनी मांगों के लिए लड़ भी नहीं सकता। इस का षड़यंत्र पिछली सरकार ने किया। यही तक नहीं, किसानों के काम आने वाले औजारों की कीमत बढ़ा दी गई। उसे सस्ते औजार नहीं दिए गए। दूसरी तरफ जो चीज किसान पैदा करता है उस के दाम सस्ते कर दिए गए। कपास का, गन्ने का उदाहरण ले लीजिए। गन्ने की कीमत 8 रुपये, 10 रुपये क्विंटल और चीनी की, गुड़ की कीमत क्या है ? इतनी महंगी ? किसान का हर बात में कदम-कदम पर शोषण किया गया, उससे वोट लिया और उसके बाद उस का शोषण किया। किसान के लिए सस्ते कपड़े बनाने चाहिए थे। गांव में किसान की जो आवश्यकता है उस की उपलिब्ध उसे गांव में ही करनी चाहिए थी। श्रीकृष्ण भगवान ने जिन्हें हम भगवान के नाम से जानते हैं, यह व्यवस्था की थी उस जमाने में कि किसान की आवश्यकता किसान के खेत पर पूरी हो उस के गांव में पूरी हो. किसान का शोषण शहर वाले व्यापारी न कर सकें इसलिए पाबन्दी लगायी कि घी दूध भी शहर में बेचने न जाएं, गांव में रखें, गांव का विकास करें।

मेरा निवेदन है कि जब तक गांवों का शहरीकरण नहीं किया जायेगा, हर गांव को शहर नहीं बनाया जायेगा, गांवों में सड़कें नहीं पहुंचायी जायेंगी तब तक गांवों का और किसान का विकास होना संभव नहीं है। मैं आप को कुछ और उदाहरण दूं। चुंगी ली जाती है, टैक्स लगाए जाते हैं। किसानों पर। मूंगफली पर, जीरे पर, धनिया पर सरकार ने टैक्स लगा दिया। टैक्स पर टैक्स सरकार लगाती रही। यहां तक कि यदि यह सरकार बनी रहती तो किसान गांव में रहता, उस पर भी टैक्स, किसान के घूमने

पर भी टैक्स, हर चीज पर टैक्स लगा देती। लेकिन अब वह चली गई।.....(व्यवधान) हम ने तो आते ही उस का टैक्स हटा दिया। 15 बीघे तक की जमीन का लगान माफ कर दिया। उस के लिए मैं जनता सरकार को बधाई देना चाहता हूं। पिछली सरकार ने क्या किया ? किसान पर सारा टैक्स बढ़ा दिया, उस का लगान बढ़ा दिया। किसान के साथ हर तरह का अन्याय किया गया। व्यापारियों को लूटने की खुली छूट दे दी गई। इस तरफ विचार होना चाहिए और उस के लिए कोई तरीका निकालना चाहिए। कोई ऐसा किसान आयोग बनाना चाहिए जिस में किसान भी हों, जानकार लोग भी हों और सरकार के भी प्रतिनिधि हों। इस प्रकार का कोई किसान आयोग केन्द्रीय स्तर पर बनाना चाहिए जो किसानों की समस्याओं पर विचार करे और उन की समस्याओं को हल करे।

अन्त में मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। गांवों में अधिक से अधिक कृषि विश्वविद्यालय और कृषि कालेज खोलने चाहिएं। किसानों के बच्चों को विस्तृत जानकारी वहां देनी चाहिए। मेरा दूसरा सुझाव है कि ग्राम सेवक अधिक से अधिक गांवों में भेजें जो किसानों को जानकारी दें कि किस तरह से वे अपनी अच्छी पैदावार कर सकते हैं और पैदावार बढ़ा सकते हैं। अच्छे बीज, सस्ते औजार, ट्रैक्टर वगैरह किसानों को उपलब्ध किए जायें। पशुधन को महत्व दिया जाये। डेयरियों का विकास किया जाये। हर गांव को सड़क से जोड़ा जाये। हर गांव में बिजली पहुंचायी जाये। बिजली की दर सस्ती की जाये ताकि किसान अपने खेत पर बिजली ले जा सके। सिंचाई की व्यवस्था की जाये। बड़े बड़े बांध बनाए जायें, नहरें निकाली जायें, किसानों को उन का पानी दिया जाये। जिस जिस गांव में पीने का पानी नहीं है वहां उस की व्यवस्था की जाये। कहीं पानी है तो वह जहरीला है, उस के पीने से फोड़े फुंसी और तरह तरह के रोग किसानों को हो जाते हैं। वहां उन के पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाये। इस का सर्वेक्षण कराया जाये कि कहां किसान के पीने का पानी नहीं है, कहां जहरीला पानी है और सर्वेक्षण करा कर वहां पीने का पानी उपलब्ध किया जाये। कितने गांवों में सिंचाई के लिए पानी नहीं है, इस का सर्वेक्षण किया जाये। गांव गांव में मंडियां बनाई जायें ताकि किसान वहां अपना अनाज बेच सकें और किसानों की छोटी छोटी आवश्यकता की चीजें उस को वहीं उपलब्ध हो सकें। जो व्यापारी हैं वे उन का शोषण नहीं करें, इस बात की व्यवस्था की जाये। जो ट्रैक्टर और औजार किसानों की खेती के काम आते हैं उन को सस्ता किया जाये। नई टैकनालाजी का ज्ञान किसानों को कराया जाये।

इस के अलावा मैं एक नई चीज बताना चाहता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं राजस्थान सरकार को, कि उस ने पहली बार पूरे देश में राजस्व अभियान और अंत्योदय योजना चलाई, जिन दो पहियों पर किसान की गाड़ी चलती है। राजस्व अभियान के अन्तर्गत उन्होंने जिन किसानों के केसेज न्यायालय में पिछले अनेक वर्षों से चल रहे थे, वकील उन को लूटते थे, तहसीलदार और कलैक्टर रिश्वत लेते थे और किसान परेशान होता था, उस के सम्बन्ध में तहसीलदार, एस० डी० एम० और कलैक्टर गांव-गांव में गये, एम० एल० ए० और एम० पी० चुने हुए प्रतिनिधि उन के साथ मौजूद रहे और वहां पर जितने मामले किसानों के अदालतों में पड़े हुए थे, उन पर निपटारा गांव की चौपाल पर बैठ कर किया। इस कार्य के लिये राजस्थान की सरकार बधाई की पात्र है।

अंत्योदय योजना के अन्तर्गत हर गांव में जो सब से गरीब पांच परिवार थे, उन को एक साल में ऊंचा उठाने की गारन्टी सरकार ने अपने ऊपर ली। पशु धन के लिये उन को

[श्री नाथू सिंह]

ऋण दिया गया, कोई और काम करना चाहे, तो उस के लिये ऋण दिया गया, इस प्रकार से एक साल में प्रत्येक गांव में सब से गरीब पांच परिवारों की गरीबी हटा दी जायेगी। इस प्रकार की योजना बनाई गई हैं। मेरा विश्वास है कि इसी प्रकार से राजस्व अभियान, अंत्योदय योजना और कोई तीसरी योजना भी जल्दी से जल्दी पूरे देश में लागू की जायेगी। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, किसान के दर्द को मैं समझता हूं। सब से पहले जनता सरकार ने बजट का चालीस प्रतिशत भाग किसानों पर खर्च करने की योजना बनाई। यदि आप हिसाब लगा कर देखें, तो 80 प्रतिशत जनता पर चालीस प्रतिशत का खर्चा और 20 प्रतिशत जनता पर 60 प्रतिशत खर्चा किया जा रहा है। इस प्रकार 80 प्रतिशत जनता, पर चालीस प्रतिशत खर्चा ज्यादा नहीं है मैं इस को कम मानता हूं.... (व्यवधान).. कांग्रेस ने जो कुछ किया, उस को वह भाग कर चली गई। जनता पार्टी को कुछ करना चाहिये। जनता पार्टी भी यदि किसानों के प्रति जागरुक नहीं रही, उस ने किसानों के आंसुओं को नहीं पोंछा तो उस का भी हाल कांग्रेस जैसा हो सकता है, क्योंकि किसान आज जाग गया है। मैं बधाई देना चाहता हूं जनता सरकार को, कि अभी उस ने जो कदम उठाये हैं, वे अच्छे हैं और आशा है आगे भी इसी तरह से किसानों के लाभ के लिये कदम उठाती रहेगी। आप ने मुझे जो समय दिया, उस के लिये धन्यवाद।

SHRI SHYAMAPRASANNA BHATTACHARYYA (Uluberia): I support this Resolution and thank Shri Arjun Singh Bhadoria for bringing this matter before this House.

Yesterday, our Prime Minister spoke on the poverty problem of Eastern U.P. and said that exploitation should end, the harijans should get land and build our economy in a new way. I want to go deeper into the matter. I want to draw the attention of our Ministers to look deep into it. We want to build our India on the basis of the Indian culture.

I should tell you one thing. When Shri Ram Chandra after having got Sita back from Ravana came back with Sita to Ayodhya, the subject—people or praja—refused to accept Sita.

They said that since Sita remained in Ravana's house, she could not be taken. The subjects demanded this. Even the sages advised Lord Ramachandra to leave her one-sixth of the produce given by the subjects for their living. For obeying their verdict, Sita was sent for *Vanvas*. That was the life of peasantry at that time.

At that time Government took the responsibility of giving irrigation to the people. That is the history of our country. In the Hindu period, this village system was not disturbed. It was also not disturbed in the Muslim period. Only one-sixth to one-fourth of the revenue, the Mahajans at that time they could not even get more than double including interest on principal.

But, when the British came, they changed the old Indian system; they took all the lands from the peasants and gave them to the landlords. The British Government took it up on themselves to change the village system which was in vogue for thousands of years and it was broken into pieces. You must understand this. After the British Rule, after thirty years of our Independence, we must feel that we are still carrying the heritage *not* of India but of British imperialism. The property system created by the British Imperialism is being carried forward by us. And, on that basis, we are trying to develop that system. We can never do that. The real basis to do that is to abolish the British system lock, stock and barrel. You have to establish in

villages of India a radical landreform by giving lands to the real tillers. I do not mean small owners. But you must take away the lands from the big owners who are not themselves cultivating the lands but who are controlling sixty per cent of the lands. Take out their lands and give them to the tribal people, the landless people and the poor peasants and help them in irrigation by giving also some implements.

Let them, the big land owners, change their occupation to industry and commerce. Then only we can rebuild our Indian system. You must be help enough to do that. You must also deeply think what India is now. I do not want to go further than this. You must understand that the people of India have broken the rule of emergency—of one lady-dictator in this country. None of us can say that we have changed India. It is the Indian people who have broken really this oppressive rule.

They are now restive and they are critical now. If you cannot change this system into a real one, people will not exclude us. Governments after Governments will be thrown out unless and until a real economic base in the rural India is established. Be careful on this point. These are the people who are making history and not the leaders. Those leaders who are deeply with the people can do something. Those who forgets the people, those who betray the people, those who cheat the toiling people, are bound to be overthrown. The Janata Party in its manifesto has pledged to end poverty, unemployment and illiteracy. In our country, technology has much developed. There are sufficient technicians. We can build on the basis of rural India. Sir, our country will not go the American way, not also the British way, but India must go the Indian way. Think of it. Think with all deep feelings and respect for the people, then and then only the Janata Government can contribute somthing. With these words, I support the Resolution.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Sir, I want to make a submission with your permission. The hon. Minister will speak now. I have to introduce my next resolution after this. Therefore, you please fix the time and tell me at what time the hon. Minister will reply.

MR. CHAIRMAN: The Minister will be called upon just now.

16.58 hrs.

[SHRI DHIRENDRANATH BASU—*in the Chair*].

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): Mr. Chairman, Sir, I have been greately benefitd by listening to the various speeches made by the hon. Members this afternoon. The main substance of these speeches is that we have not treated the agriculturists fairly and that we should do so now. It is perfectly correct that during the last 30 years, we have been somewhat indifferent towards the rural areas—and the development of rural areas—which, of course, include the agriculturists. But now when we try to repair the damage that has been done to the rural areas, and to the farmers, for all this long period of time, it should be realised that it would take time. What I would like to urge upon the House is that the basic policy that has been accepted by the Government is the elimination of poverty and also of unemployment. Both these exist in the maximum proportion in this country, in the rural areas. And therefore all our policies must be so designed as to generate employment in the rural areas and also ensure that the farmer who is the main producer in the rural areas is enabled to bewcome more prosperous. How does he become more prosperous? He can only become more prosperous if he is able to produce more, if he is able to get more yield per acre of his land and

[Shri H. M. Patel]

if he is able to get for what he produces a fair and reasonable price. The mover of the resolution has used the term 'parity' in his resolution. The term 'parity' means that in any price that he gets, account would be taken of the inputs. Whatever price he has to pay for them, he should be able to recover when he sells the produce. Therefore, the emphasis should be on ensuring the farmer a reasonable remunerative price for what he produces. These are the two things that we have to see that the farmer gets the maximum yield per acre, and that for whatever he produces gets a reasonable price. How does he get the maximum yield? He can get the maximum yield if we take care to see that he gets the necessary inputs. The most important input is water and it is therefore that the greatest emphasis is going to be laid in our planning to the, maximisation of irrigation facilities. Only if there is assured water supply can the farmer derive the fullest benefit from his inputs such as fertilisers, improved seeds, etc.

17 hrs.

Similarly we are laying emphasis on producing fertilisers in adequate quantities as also the improved seeds which he may require. Because fertilisers bring in certain ills such as pests, etc., he must be ensured that pesticides and weedicide reach him in sufficient quantities at the right time. It is the government's express policy to provide all these things. It seems to me that so far as government's policy is concerned, it is in the direction in which the hon. Mover wants its; that seems to be the position at least as I see it.

But what is to be realised is this. Agriculture is a state subject. So far as the Centre is concerned, it can provide the necessary resources and that is why it has decided to increase substantially the allocation of resources for the rural areas, for agriculture. It can also make arrangements fo research in agriculture, for the production of improved seeds, for new varieties of seeds so that the maximum yield can be achieved. It can similarly plan and make available resources for the organisation of a satisfactory extension system and also provide finances for agricultural universities and agricultural education. But the real work for improvement of agriculture, for the development of rural areas has to be done in the states and to the extent that the state government are enthusiastic in this matter and fall in line with the policies which we lay down, will we be able to achieve our objective. For instance, the budget of the current year is pointing to the direction in which we want to move and we have made special provision for drinking water supply and for rural approach road. Why did we do that? Because we wanted to point out that we attach special importance to rural development and these are especially the two directions in which we want early achievement. A large percentage of our villages in many States are without approach roads which can enable farmers to take their products to mandis and other places. The approach roads should be given the highest priority and we should try to see that all the villages had approach roads, all weather roads which will enable them to use them for 12 months in a year. It will take time.

How much time will depend very much upon the speed at which the State Governments function. The same is the case with drinking water supply. I am glad to say that a number of States have moved quite enthusiastically in these directions and because of that, I feel optimistic about the success of the policy which we wish to pursue. As things stand today in the first year of our assumption of power, I would only put before this House the fact that we have adopted the right policy in respect of the rural areas and rural development and we have assured everybody that we will attach the highest importance to the most expeditious and

speedy progress in rural development and we have also in these plans made it known that we mean business, that we intend steadily to increase the allocation of available resources for the purpose of rural development. I hope that this particular exposition of the policy which has already been announced will satisfy those who have spoken today that this Government does mean business in so far as the rural development is concerned and in so far as the interests of the farmers are concerned.

Reference has been made to prices in a general way by Mr. Kanwar Lal Gupta. But I think that particular aspect pertains more to the urban areas and much of his arguments, were with respect to the urban areas, etc. Certainly there can be no two opinions on this. The prices of essential commodities must be controlled and every possible step must be taken to see that the essential commodities are made available in adequate quantity and at reasonable prices. I also agree with what he said regarding the stamping of the prices on cloth. It is a deficiency which we have realised and about which we hope to take very early remedial measures. I would assure him that in all these directions we are moving with speed and not just drifting. That is all I can say.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I would like to ask two questions. I have made two suggestions, one regarding the ceiling on profit and the other som e restriction on the exhibition of riches. What have you got to say about these two things?

SHRI H. M. PATEL: Certainly, as matter of fact, I thought this is implied in what I have said. You cannot achieve a measure of control over the prices of essential commodities, etc., unless we seek to ensure a certain measure of ceiling on profit. But how do we do it? There is no one method which we can adopt. It is not possible to have any uniform system which will be applicable to every commodity. In the same way about exhibition of riches, what he said, I think, is perfectly correct. So far we have been saying that this should be avoided. But what measures we take in order to see that this is prevented, this is discouraged, I think, you must have patience to see that. We will take necessary steps.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): Before these long term policies are implemented, I hope the state of affairs which is continuing for the last nine months will not be repeated. But what about the Public Distribution System of the essential commodities? Have you got a sort of any crash programme? Have you got an immediate policy to distribute essential commodities to the people through the Public Distribution System, because the private trade has not been able to serve the interests of the people? What is the Government's policy on this and when are you going to achieve it?

SHRI K. CHANDRAPPAN: There is the serious problem of parallel economy of black money. Is the government taking any concrete drastic steps like demonetisation to overcome it?

SHRI H. M. PATEL: About the public distribution system, I can only repeat what my colleague, Shri Mohan Dharia said. We should first make available essential commodities and then distribute them through the public distribution system. We can only do that in respect of commodities which are available in adequate quantities. We can do that in respect of foodgrains, which we are doing. We can do that in respect of sugar, which we are endeavouring to ensure. We can do it in respect of cloth for which there should be no shortage. I deliberately say, there should be no shortage. We will take steps hereafter to ensure it. But it may not be so easy to do so in respect of oil this year but I hope we shall be able to do it in respect of edible oil also because we have made a year-wise plan and we have made it clear that having made that plan, to the extent to which we estimate there would be shortage we will

[Shri H. M. Patel]

import oil. Therefore, to my mind that also can be included among commodities which we should be able to make available. There will still be some commodities of which there may not be adequate supply. To make those things available through the public distribution system would be to ask something that would be unwise even to attempt to do; there we have to take some other measures.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: (Diamond Harbour) : Where is your public distribution system? Mrs. Gandhi had systematically dismantled it. Although you have been in power for 7 or 8 months, you have not done anything or doing anything which could impress us.

SHRI H. M. PATEL: I think there will be and there is a public distribution system. There will be an improved public distribution system. I was only pointing out that along with that, what is more important is that we should have the commodities to put in that public distribution system.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: The West Bengal Government wanted to bring the entire population under statutory rationing, but because of your new policy about removal of rice zone, we cannot even extend assured supply to the modified ration shops. That is why we are having disquieting moments. I am glad as a policy you have announced that it should be done through the public distribution system, but we want you to take vigorous steps to implement it.

SHRI H. M. PATEL: I entirely agree and I shall see that that point is communicated to my colleague whose business it should be to do it. I will also make available the financial resources necessary for this purpose.

About black money, there is no simple remedy for doing away with it. It is something which continues to be generated all the time. Therefore the method we adopt should be such as would prevent the continuous generation of black money. That is not going to be achieved in our view by any process of mere monkeying about with the monetary currency system. It can only be done by ensuring that there is no shortage and there is more production. There are less opportunities for transactions outside the normal commercial business transactions. These are the things which we have to try to do or prevent and this is what we are trying to do. We are not closing our eyes to the fact that black money is something of a very major problem and it has to be faced, but it must be faced in a manner which would really achieve the object we have in view.

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : सभापति महोदय, मैं ख़ज़ाना मंत्री के तथ्यहीन और निर्गुण तर्कों को सुन कर आश्चर्य चकित हूं। उन्होंने वही पुराने, घिसे-पिटे तर्क देकर सदन को बताया है कि गेहूं आदि किसान का कृषि-उत्पादन राज्य का विषय है। अगर गेहूं और चावल राज्य का विषय है, तो साथ ही साथ किसान ही गन्ना पैदा करता है, और गन्ने से जब चीनी बन जाती है, तब केन्द्रीय सरकार उसे कन्ट्रोल में ले लेती है—तब वह केन्द्र का विषय बन जाता है। जो पिछले तीस वर्षों से पुराने तंत्र के तर्क रहे हैं, ख़ज़ाना मंत्री को उन से हट कर इस देश की आत्मा को छूने के लिए नये तर्क देने होंगे और नई व्यवस्था स्थापित करनी होगी।

SHRI H. M. PATEL: I think he has misunderstood my point. What I said about States' responsibility is that so many of the developmental tasks that have to be done have to be done by the State Governments and to the extent that they show speed in the implementation of our plans and projects, would be able to move towards our goal successfully. I did not say that we disown responsibility. I just want to explain this.

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : मैं खज़ाना मंत्री को कहना चाहता हूं कि देश की ग़रीब जनता, और विशेषकर किसान, यह महसूस न कर पायें कि गरीब किसान का दुख और उनकी आत्मा की पीड़ा हमारे खज़ाना मंत्री और जनता पार्टी की सरकार के मन को नहीं छू रही है । देश की जनता को, और अन्नोत्पादन करने वाले किसानों को, यह महसूस होना चाहिए---और उन्हें यह महसूस कराना चाहिए---कि जनता पार्टी की गवर्नमेंट उनके लिए जो कुछ भी सम्भव है, वह करना चाहती है, और उसके लिए प्रयत्नशील है ।

मैं महसूस करता हूं कि पिछले आठ महीनों में उन लोगों के लिए सिर्फ़ आश्वासनों की पोटलियां खोली गई हैं । निर्गुण भाषणों और आश्वासनों से पेट नहीं भरता है । पेट कोई सगुण कार्य करने से भरता है । इसलिए मंत्री महोदय सगुण रूप में कोई ऐसा काम उपस्थित करें, जिससे देश की ग़रीब जनता, और विशेषकर किसान, यह महसूस करने लगें कि उनके लिए कुछ किया जा रहा है ।

जो संकल्प आपके सामने उपस्थित हैं, उसमें कुछ त्रुटियां लोक सभा सचिवालय की तरफ़ से हैं । इस प्रस्ताव के मूल रूप को ठीक से उपस्थित नहीं किया गया है । जो प्रस्ताव इस सदन में लोक सभा सचिवालय की तरफ़ से दिया गया है, वह ऐसा है कि अगर देश का किसान उसे पढ़ेगा, तो वह मेरे विरुद्ध तो हो ही जायेगा, साथ ही साथ वह जनता पार्टी की सरकार का भी विरोध करने लगेगा । जैसे हमने लिखा कि मेटी मुनाफ़ा और बड़े कृषि फार्म मालिकों के हितों पर आघात करना होगा और इस प्रस्ताव में है कि बड़े व्यापारियों तथा किसानों के मुनाफ़ों पर अंकुश लगाया जा सके। यह जो संकल्प है यह किसानों के मुनाफ़े पर अंकुश लगाने के लिए नहीं बल्कि उनको उचित मुनाफ़ा दिलाने के लिए है। जो मूल प्रस्ताव है मैं उसे पढ़ देता हूं जिससे कि पटेल साहब को इस पर निर्णय लेने और इसे सदन से पास कराने में सुविधा हो और जो हमारे सदस्य यहां पर उपस्थित हैं उनको भी पूरी की पूरी जानकारी हो जाये क्योंकि सदन के अन्दर जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया है वह अधूरा है, निष्प्राण है और उसकी आत्मा को निकाल कर निर्जीव शरीर को यहां पर उपस्थित किया गया है । इसलिए संकल्प जैसा मूल रूप में है उसे मैं पढ़ देता हूं : सदन को जरूरी चीजों के चालू दामों पर गहरी चिन्ता है ।

यह सभा अनुभव करती है कि कांग्रेस राज के 30 वर्षों में देश के किसानों और ग़रीब जनता की लगातार उपेक्षा की गई है ।

सरकार ने कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन में संतुलन न रख कर कृषि पैदावार और उसके मूल्यों में लगातार गिरावट और औद्योगिक उत्पादन में नकली व्यय दिखा कर उसके दामों में निरन्तर बढ़ोतरी की है ।

दाम और आमदनी जीवन-रथ के दो पहिये होते हैं, जहां उनका साथ गड़बड़ाया, गृहस्थी टूटी । देश की अधिकतर गृहस्थियां दामों की दुर्नीति के कारण चल नहीं पा रहीं । निस्संदेह किसी भी स्वतंत्र और गरीब देश का सब से बड़ा प्रश्न दामों की लूट के खात्मे का है ।

सरकारों के बढ़ते हुए कर और सेठों के बढ़ते हुए मुनाफों ने कारखानों में बनी पहनने, ओढ़ने, खाने और जीवनोपयोगी उपभोक्ता वस्तु के बिक्री दाम लागत खर्च से कई गुना बढ़ा दिए हैं । इसी तरह, अनाज के दाम फसल कटते ही गिरने और उसके बाद लगातार बढ़ते रहने से सरकारी कर और

[श्री अर्जुन सिंह भदौरिया]

सेठों के मुनाफ़े में लगातार बढ़ोतरी होती रही है । फसल दाम की तुलना में मोटे अनाजों के दामों में 25–30 पैसे प्रति किलो और महीन अनाज में 30 से 50 पैसे प्रति किलो तक की मारक बढ़ती हर साल होती रही है । फसल के बाद भयंकर इस बढ़ती में देश के लोगों की कैसी नारकीय दुर्गति हुई है और उसे वह कैसे सह लेते हैं यह सब आश्चर्य की बात है ।

यह सदन संकल्प करता है कि खेत की पदावार और मशीनी पैदावार में संतुलन (परिटी) स्थापित की जायें ।

(1) किसी भी अनाज का लागत दाम दो फसलों के बीच 10 पैसे प्रति किलो से अधिक नहीं बढ़े ।

(2) कारखानों में बनी किसी भी जीवनोपयोगी वस्तु का बिक्री दाम लागत खर्च से डयौढ़े से ज्यादा किसी हालत में न हो ।

(3) किसान को उसके अनाज और कच्चे माल का ऐसा दाम मिले जो लागत खर्च और जीवन निर्वाह को पुसाये (पड़ता पड़े) ताकि खेतिहर और औद्योगिक वस्तुओं के दामों में संतुलन और समता कायम हो ।

सदन भली भांति जानता है कि इस दाम नीति को कारगर करने के लिए सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने होंगे ।

सेठी मुनाफा और बड़े कृषि फार्म मालिकों के हित पर आघात करना होगा । विभिन्न प्रकार की निजी आमदनी और सरकारी नौकरी की सीमा बांधनी होगी । देश की कर प्रथा में ऐसे बुनियादी परिवर्तन करने होंगे, जिससे जीवनोपयोगी वस्तुओं पर लगने वाले बहुत से कर जैसे चुंगी, बिक्री-कर वगैरह कम होंगे । बड़े घरानों करोड़पति सेठों और बड़े फार्म मालिकों के रहन-सहन में फर्क लाने के साथ साथ सब के औद्योगिक इंतजाम और पद्धतियों को बदलना होगा । जहां जरूरत हो और संभव हो, चौखम्भा और स्वायत्त समाजीकरण के जरिए ही इस दाम नीति को उजागर और कारगर करना होगा ।

सदन का मत है––"जिन दलों ने ऊपरी दिखावटी और नकली आधुनीकरण और औद्योगीकरण का उद्देश्य अपनाया है, उन के द्वारा लोक कल्याणकारी दाम नीति का चलन संभव नहीं है । चाहे कांग्रेस अथवा सी पी आई दोनों ही अपने दिखावटी आधुनीकरण का गीत क्यों न गाते हों ।"

"यह सदन इस लोक कल्याणकारी दाम नीति से देश में जनता राज्य के माध्यम से जनता को बेहतर जिन्दगी देने और किसानों को उनकी कृषि पैदावार का उचित मूल्य दिलाने को कृत संकल्प है ।"

SHRI H. M. PATEL: Sir, he must have been satisfied that I accept the Spirit behind his Resolution. Now, I would request him to withdraw it.

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : अगर पटेल साहब, जिनका पुराना संसदीय अनुभव है, केवल इस सदन को ही नहीं सारे देश को यह आश्वासन दे रहे हैं तो मैं इस आशा के साथ प्रस्ताव वापिस ले रहा हूं कि जनता पार्टी की सरकार इस सम्बन्ध में निरन्तर, लगातार और साथ ही साथ आज से ही मुस्तैदी के साथ क्रमबद्ध कदम उठायेगी ।

MR. CHAIRMAN: As regards other amendments, are the hon. Members concerned withdrawing them.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Have they the permission of the House to withdraw the amendments?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

Amendments Nos. 2, 3 and 6 were, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN : Has Shri Bhadoria the permission of the House to withdraw his Resolution?

SOME HON. MEMBERS : Yes.

The Resolution was, by leave, withdrawn.

17.27 hrs.

RESOLUTION *RE.* STEPS TO IMPROVE THE ECONOMY AND TO REDUCE INEQUALITIES OF INCOME, ETC.

MR. CHAIRMAN : Now Item No. 2, Shri Kanwar Lal Gupta.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : I beg to move:

> "This House urges upon the Government to take effective steps to improve the economy of the country and to reduce the inequalities of income, wealth and personal consumption."

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) : I have given a notice in writing. Let me make a submission.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I have moved my Resolution. It should be considered next time.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur) : Sir, the motion of Mr. Jyotirmoy Bosu is very important. Such a motion has not been, subject to correction, discussed recently in this House. Now, there is a problem of bureaucracy and technocracy and this is now agitating the minds of the people and affecting different branches of administration. Now in every sphere this is happening. Therefore, our request is, let us try to have both these matters discussed on the floor of this House. Now, already our colleague, Mr. Gupta, has moved his Resolution. If it is adjourned and that is moved, we can discuss both of them. There has been a precedent like that in the past. Both the motions can be considered.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : **

SHRI KANWAR LAL GUPTA : On a point of order. I have moved my Resolution. I think, unless it is considered and passed the other Resolution cannot be moved. May I request you not to allow him to move the Resolution?

SHRI JYOTIRMOY BOSU : **

SHRI JYOTIRMOY BOSU : I have given the motion.

MR. CHAIRMAN: You wrote to the Speaker and the Speaker has given a note here that unless the second Resolution is considered, it cannot be taken up.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : I have given a motion in writing in that I have said that I want to move that the debate on Item No. 2 be adjourned after it is moved and also Rules 29 and 30 be suspended, to protect my Resolution as an exceptional case. In that connection, I read the motion. **

SHRI KANWAR LAL GUPTA : It is already 5.30. It is not proper. My Resolution should be considered.

(*Interruptions*)

SHRI JYOTIRMOY BOSU : There is a clear case if you see the debate of April 11, 1975.

A resolution tabled by a Member of this House was allowed. Now, Mr. Chairman, kindly see the pages 366 and 367 of the Debates dated 11th April, 1975.

(*Interruptions*)

**Expunged as ordered by the Chairman.